https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'देश को नरेन्द्र मोदी जैसा ही पीएम चाहिए जो सबका विकास करे'

वर्ष-14, अंक-07 01-15 अप्रैल, 2019 (पाक्षिक) ₹20

चौकीदार वो जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों से लड़े

'अपना टाइम आ गया है और ये समय है आपके पास के वोटिंग सेंटर पर जोश हाई करने का'

एजेंडा 2019 - नेतृत्व का मुद्दा

मनोहर पर्रिकरः सादगी को आत्मसात करने वाले मुख्यमंत्री

पणजी (गोवा) में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

पणजी (गोवा) में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

पणजी (गोवा) में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देते केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी

आगरा (उत्तर प्रदेश) में विजय संकल्प रैली के अवसर पर जनाभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में एक रोड शो के दौरान लोगों से मिलते केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाला हर व्यक्ति चौकीदार है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 मार्च को 'मैं भी चौकीदार' अभियान की शुरुआत की। अपने ट्वीट में श्री मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे हर भारतीय एक चौकीदार है।

वैचारिकी

जनसंघ ही क्यों? 12

श्रद्धांजलि

नहीं रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर 14

लेख

डॉ. लोहिया की याद में... 17

अपना टाइम आ गया है और ये समय है आपके पास के वोटिंग... 18

एजेंडा 2019 - नेतृत्व का मुद्दा 20

मनोहर पर्रिकर: सादगी को आत्मसात करने वाले मुख्यमंत्री 24

भरोसे और विकास के दो बरस: यूपी की भाजपा सरकार ने तमाम... 26

अन्य

कैबिनेट ने जैव चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम को पांच साल और आगे बढ़ाने को मंजूरी दी 07

पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 2 करोड़ से अधिक ... 13

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना... 16

देश को नरेन्द्र मोदी जैसा ही पीएम चाहिए जो सबका विकास करे... 28

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई 29

लोकतंत्र के लिए चार अनुरोध 30

संस्थाओं का सम्मान और संस्थाओं की अवमानना: दो परस्पर... 32

08 प्रमोद सावंत बने गोवा के नए मुख्यमंत्री

गोवा विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। गत 18 मार्च 2019 को उन्होंने गोवा राजभवन में मुख्य मंत्री पद की...

12 किफायती मकानों के लिए 1 प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने हेतु जीएसटी परिषद ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय

जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक 19 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई। जीएसटी...

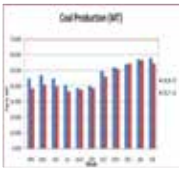

14 अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयला उत्पादन में 8.0% की वृद्धि

अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयले का उत्पादन 638.46 मिलियन टन (एमटी) रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में...

31 विपक्ष आतंकवाद के समर्थकों की शरणस्थली है: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा आतंकवादी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में भारतीय...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ है। प्रेस से पार्लियामेंट तक। सोल्जर्स से लेकर फ्री स्पीच तक। कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक। कुछ भी नहीं छोड़ा।

@AmitShah

2019 का लोक सभा चुनाव देश के 50 करोड़ गरीबों के कल्याण का चुनाव है। देश से भ्रष्टाचार और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का चुनाव है और यह सिर्फ़ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही कर सकती है।

@arunjaitley

आज एक ऐतिहासिक अवसर है जब भारत को अपने विकास की रफ्तार को अगले 10 वर्षों तक बनाए रखना है ताकि आर्थिक भंगुरता को दूर कर एक विकसित राष्ट्र बन सके।

facebook

कांग्रेस के शासन में नियम-कानून को किनारे रखकर विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे जिन बड़े लोगों को बैंकों से हजारों करोड़ रुपए दिए गए थे, उन भगोड़ों को विदेशी धरती पर भी पकड़ा जा रहा है। बेनामी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। काली कमाई से बने बंगले ध्वस्त किए जा रहे हैं। चौकीदार की सख्ती से सहमे चोरों ने महागठबंधन बनाया है, लेकिन वे जनता के गुस्से से बच नहीं पाएंगे।

— **सुशील कुमार मोदी**

देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करते हुए हमारी सरकार ने दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 2 साल में हमने युवाओं, किसानों, महिलाओं की बेहतरी के लिए प्रयास किए हैं। हमारा फोकस रोजगार बढ़ाने, उद्योगों का विस्तार करने, पहाड़ और मैदान के विकास की खाई को पाटने पर है।

— **त्रिवेन्द्र सिंह रावत**

कांग्रेस देश से माफी मांगे

देश में एक अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति बन रही है। कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों के लिए देश की सेना के पराक्रम पर प्रश्न खड़े करना एक आदत सी बन गई है। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र अपने राजनेताओं की इन शर्मनाक राजनीति को न तो सहन कर सकता है, न ही उन्हें देश की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने दे सकता है। कांग्रेस जानबूझकर अपने नेताओं को ऐसे प्रश्न करने की छूट दे रखी है जिससे हमारी सेना का आत्मविश्वास डिग जाये। क्या कोई देश के जवानों के बलिदान पर राजनीति करने की सोच भी सकता है? क्या कोई हमारी पराक्रमी सेनाओं पर प्रश्न कर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने की सोच सकता है? क्या कोई दल पाकिस्तान की भाषा बोल उसके पक्ष के समर्थन करने का दुस्साहस कर सकता है? यदि कोई इस तरह की राजनीति के बारे में सोच भी सकता है, तो यह केवल यह दर्शाता है कि उसकी सोच कितनी सड़ चुकी है और उस सड़ांध की दुर्गंध अब देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांग्रेस ने वो पाप किये हैं जिसे न तो भुलाया जा सकता है न ही जिसकी माफी हो सकती है।

सैम पित्रोदा का बयान न केवल अत्यंत निंदनीय है, बल्कि यह कांग्रेस की मानसिकता को भी दर्शाता हैं। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बारे में यह कहना कि 'इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं' सैम पित्रोदा की घृणित एवं शर्मनाक मानसिकता का परिचायक है। साथ ही, सेना से हवाई हमले का सबूत मांगकर एक बार फिर सेना का अपमान करने का प्रयास हुआ है। आतंकी प्रशिक्षण कैंपों पर हवाई हमले को सैम पित्रोदा 'गलत' मान सकते हैं, परन्तु शायद उन्हें नहीं पता कि पूरा देश इस कदम के समर्थन में है। यह अब स्पष्ट है कि क्यों कांग्रेस आतंकवाद का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाई और 26/11 मुंबई आतंकी हमले पर हाथ पर हाथ धरे बैठे रही। कांग्रेस नेतृत्व के पास न तो आतंकवाद से लड़ने का जज्बा है और न ही राजनैतिक इच्छाशक्ति। वास्तव में आज कांग्रेस में वे लोग हावी हैं जो आतंकवाद का बचाव करते हैं और उसे समय–समय पर उसे अपना बौद्धिक समर्थन देते रहे हैं।

पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट में वायुसेना के जबरदस्त प्रहार पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है, उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस न तो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की क्षमता रखती है और न ही जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान का सामना कर सकती है।

यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि सोनिया–राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस आतंकवाद, आईएसआई एवं पाकिस्तान तक के बचाव से पीछे नहीं हट रही है। भारतीय वायुसेना के पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर शौर्यपूर्ण हमले पर सैम पित्रोदा के प्रश्नों को राहुल गांधी के बयान से जोड़कर देखना चाहिए, जिसमें वायुसेना से हर प्रश्न के उत्तर की मांग की गई थी। यह कांग्रेस की रणनीति है कि वायुसेना पर प्रश्न खड़े कर उसका अपमान किया जाय। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का शर्मनाक बयान जिसमें उन्होंने वायुसेना का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे आतंकी ठिकाने तबाह करने गये थे या पेड़ उखाड़ने, की देश में कड़ी भर्त्सना हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह के द्वारा सेना से सबूत मांगना एवं उन पर कटाक्ष करना देश अभी तक भूला नहीं है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का निंदनीय बयान कभी भूला नहीं जा सकता। सपा नेता रामगोपाल यादव का पुलवामा के बलिदानियों पर दिए गए बयान से यह प्रमाणित होता है कि वोट–बैंक की राजनीति के लिये ये नेता कितने हद तक नीचे गिर सकते हैं।

पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट में वायुसेना के जबरदस्त प्रहार पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है, उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस न तो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की क्षमता रखती है और न ही जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान का सामना कर सकती है। अपने राजनैतिक हितों के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय हितों को भी दांव पर लगा सकती है और अपने बयानों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन भी कर सकती है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि आज जब पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल आतंकवाद, आईएसआई एवं पाकिस्तान के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस राष्ट्रीय हित में दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकती है। राष्ट्रीय हितों की अनदेखी तथा सेना का अपमान करने के लिए कांग्रेस को तुरंत पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को अविलंब पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि अब भी वे देश से क्षमा मांगने से चूक जाते हैं, तो जनता उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वे कभी भूल नहीं पायेंगे। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाला हर व्यक्ति चौकीदार है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 मार्च को 'मैं भी चौकीदार' अभियान की शुरुआत की। अपने ट्वीट में श्री मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे हर भारतीय एक चौकीदार है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अक्सर स्वयं को ऐसा 'चौकीदार' बताते आए हैं जो भ्रष्टाचार को अनुमति नहीं देगा और न ही स्वयं भ्रष्टाचार करेगा, लेकिन कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित रहने की पुरानी आदत है। इसके नेता 'चौकीदार' शब्द को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पूर्व भी 2014 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेताओं द्वारा अपमानजनक ढंग से श्री नरेन्द्र मोदी पर 'चायवाला' टिप्पणी की गई थी, जिसका देशभर में विरोध हुआ था। इस बार भी भाजपा ने 'चौकीदार' को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा अमर्यादित बयानबाजी के विरोध में 'मैं भी चौकीदार' अभियान की शुरुआत की है, जिससे बड़ी संख्या में लोग तेजी से जुड़ रहे हैं।

यह अभियान श्री नरेन्द्र मोदी की मजबूत और निर्णायक नेता वाली छवि को और ज्यादा निखार रहा है। इसमें श्री मोदी ने आम आदमी को कहा कि उनका चौकीदार देश की सेवा में अडिग खड़ा है, लेकिन वो अकेला नहीं है। देश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाला चौकीदार है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति देश की प्रगति के लिए जमकर मेहनत कर रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर हर भारतीय बोलेगा 'मैं भी चौकीदार'।

'मै भी चौकीदार' ट्वीट करने के ठीक एक दिन बाद ही श्री मोदी ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़कर चौकीदार नरेन्द्र मोदी नाम रख लिया। इसके तुरत बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भी अपने ट्वीटर हैंडल पर

अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ लिया। कुछ घंटों में ही मंत्रियों और सांसदों ने अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ लिया।

'मैं भी चौकीदार' अभियान में दो दिनों के अंदर ही 2 मिलियन ट्वीट हो चुके थे। इस पर कुल 16,800 मिलियन इंप्रेशन आए। प्लेजेस भी अब तक 5 लाख से ऊपर रहे। मोदीजी का ट्वीट किया हुआ वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगभग 10 मिलियन बार देखा गया। 'मैं भी चौकीदार' कैंपेन दुनियाभर में एक दिन और भारत में लगातार दो दिनों तक टॉप ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर और फेसबुक पर नेट यूजर्स ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाना शुरू कर दिया। आम नेटीजन के बीच भी 'हैशटैग मैं भी चौकदार' वायरल हो गया।

इस अभियान के तहत एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें जीवन के हर क्षेत्र से आए लोगों को देश के सजग प्रहरी के तौर पर 'चौकीदार' बनते दिखाया गया है। ताकि मोदीजी की ही तरह देश के लिए वह अपने हिस्से का योगदान दे सकें।

रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, 'अपने देश के चौकीदारों के तौर पर कैशलेस वित्तीय ट्रांजैक्शन के जरिए हम स्वच्छ अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

दशकों से भ्रष्टाचार और कालेधन के प्रकोप से देश पर बुरा असर पड़ा है। बेहतर भविष्य के लिए इसे खत्म करने का समय आ गया है। 'हैशटैग मैं भी चौकीदार' 'हैशटैग चौकीदार फिर से'।'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भी इस अभियान से जुड़ा एक वीडियो जारी किया जिसमें लोगों को आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, 'जिसने स्वच्छता को नैतिक मूल्य बनाया वह चौकीदार कहलाया। अपने पूरे दिल से कहिए- 'चौकीदार फिर से।'

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने लिखा कि देश बदला, विश्वास बदला। हर व्यक्ति में एक चौकीदार मिला। वहीं, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि 2013 के मुकाबले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में सदाबहार वनों का क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। नदियों का प्रदूषण कम करने के लिए 18 प्रभावी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। गंगा और उसकी सहायक नदियों पर 44 जल निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए।

केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट किया कि गंदगी, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों से देश को मुक्त कराने के लिए जो कोई भी अपना योगदान दे रहा है, वह चौकीदार है। ■

कैबिनेट ने जैव चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम को पांच साल और आगे बढ़ाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मार्च को जैव चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम (बीआरसीपी) और वेलकम ट्रस्ट (डब्ल्यूटी)/डीबीटी इंडिया एलायंस को इसकी आरम्भिक 10 वर्षीय अवधि (2008-09 से 2018-19 तक) से आगे बढ़ाकर नये पंचवर्षीय चरण (2019-20 से 2023-24 तक) में भी जारी रखने को मंजूरी दी। उधर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने अपनी प्रतिबद्धता डब्ल्यूटी की तुलना में दोगुनी बढ़ा दी। इस निर्णय से कुल वित्तीय बोझ 1092 करोड़ रुपये का पड़ेगा जिसमें डीबीटी और डब्ल्यूटी क्रमशः 728 करोड़ एवं 364 करोड़ रुपये का योगदान करेंगे।

इस कार्यक्रम ने 1:1 साझेदारी में अपने 10 वर्षीय वित्त पोषण के दौरान भारत में अत्याधुनिक जैव चिकित्सा (बायोमेडिकल) अनुसंधान में उच्चतम वैश्विक मानकों वाली प्रतिभाओं के सृजन एवं शिक्षण से संबंधित अपने उद्देश्यों को पूरा कर लिया है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां और अनुप्रयोग संभव हो पाए हैं।

बीआरसीपी से विदेश में काम कर रहे बेहतरीन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए स्वदेश वापस आना आकर्षक बना दिया है। इसके साथ ही बीआरसीपी की बदौलत भारत में कई स्थानों पर ऐसे केन्द्रों की संख्या काफी बढ़ गई है, जहां विश्वस्तरीय जैव चिकित्सा अनुसंधान किए जाते हैं।

इस कार्यक्रम के विस्तार वाले चरण के दौरान इस क्षमता को बढ़ाने का क्रम जारी रखा जाएगा और इसके साथ ही भारत में स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए नैदानिक अनुसंधान और कार्य को भी सुदृढ़ किया जाएगा। भारत सरकार की बढ़ी हुई हिस्सेदारी के साथ इस कार्यक्रम को जारी रखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी अपेक्षित परिणाम हासिल हो पाएंगे। ■

स्टार्टअप सहयोग पर भारत और कोरिया गणराज्य के बीच समझौते को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मार्च को स्टार्टअप सहयोग पर भारत और कोरिया गणराज्य के बीच सहमति पत्र पर पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दी। इस सहमति पत्र पर फरवरी 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस सहमति पत्र से दोनों देशों के स्टार्टअप उद्योगों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में आसानी होगी और बढ़ावा मिलेगा, जो उनके राष्ट्रीय कानूनों और नियमनों तथा ऐसे किसी प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर आधारित होगा, जो दोनों देशों से संबंधित हों।

प्रमोद सावंत बने गोवा के नए मुख्यमंत्री

गोवा विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। गत 18 मार्च 2019 को उन्होंने गोवा राजभवन में मुख्य मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा ने उन्हे शपथ दिलवाई। विदित हो कि गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर का 17 मार्च 2019 को निधन हो गया था।

नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने कहा कि मुझे सभी सहयोगियों के साथ एक स्थिरता और आगे बढ़ना है। अधूरे कामों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं मनोहर पर्रिकर जी के जितना काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना संभव हो सके काम करने की कोशिश करूंगा।

एमजीपी के सर्वश्री मनोहर अजगांवकर, भाजपा के मौविन गोडिन्हो, विश्वजीत राणे, मिलिंद नाइक और निलेश कैबरल, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विनोद पल्येकर और जयेश सालगांवकर और निर्दलीय विधायक रोहन खैतान और गोविंद गावडे ने भी राजभवन में राज्य कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदीन धवलिकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजई सरदेसाई सहित 11 नेताओं ने भी राजभवन में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

इससे पहले श्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, मैं इसे हर संभव तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करुंगा। आज मैं जो कुछ भी हूं सब मनोहर पर्रिकर की वजह से हूं। वे ही मुझे राजनीति में लाए थे, मैं आज स्पीकर और अब मुख्यमंत्री बन गया हूं।

प्रमोद सावंत व उनकी टीम गोवा के लोगों के सपनों को पूरा करने की अपनी यात्रा की शुरुआत कर रही है, इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि वे बीते कुछ सालों में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और गोवा के विकास को बढ़ावा देंगे।

– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनकी टीम को शपथ ग्रहण की बधाइयां। मुझे यकीन है कि यह नया नेतृत्व समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ गोवा के लोगों की सेवा करना जारी रखेगा। मेरी शुभकामनाएं।

– अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

बहुमत परीक्षण में रहे सफल

गोवा के नए मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत विधानसभा में बहुमत परीक्षण में सफल रहे। भाजपा ने अपने सहयोगियों की मदद से बहुमत के लिए जरूरी 19 सीटों से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया। भाजपा और उसके सहयोगियों को 20 वोट मिले। जबकि कांग्रेस खेमे को कुल 15 वोट मिले। ■

किफायती मकानों के लिए 1 प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने हेतु जीएसटी परिषद ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय

जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक 19 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई। जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 33वीं बैठक में किफायती मकानों के लिए 1 प्रतिशत और किफायती मकानों को छोड़ निर्माणाधीन मकानों पर 5 प्रतिशत की घटी हुई प्रभावी जीएसटी दर हेतु की गई सिफारिशों पर अमल के लिए विचार-विमर्श किया गया। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने इस दिशा में अग्रसर होने के लिए संबंधित तौर-तरीकों के बारे में निर्णय लिया, जो निम्न है।

मौजूदा परियोजनाओं के संबंध में विकल्प

प्रमोटरों को उन मौजूदा परियोजनाओं (ऐसी इमारतें जिनके निर्माण कार्य के साथ-साथ वास्तविक बुकिंग भी 1 अप्रैल, 2019 से पहले ही शुरू हो गई है) पर पुरानी दरों (आईटीसी के साथ 8 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत की प्रभावी दर) से ही टैक्स अदा करने का एकबारगी विकल्प दिया जाएगा जो 31 मार्च, 2019 तक पूरी नहीं हो पाएंगी।

इस विकल्प को निर्धारित समयसीमा में केवल एक बार ही अपनाया जा सकेगा और जिन मामलों में निर्धारित समयसीमा के भीतर इस विकल्प को नहीं अपनाया जाएगा उन मामलों में नई दरें लागू की जाएंगी।

नई टैक्स दरें

नई परियोजनाओं के साथ-साथ नई व्यवस्था के तहत टैक्स अदा करने का उपर्युक्त विकल्प अपनाने वाली मौजूदा परियोजनाओं पर लागू नई टैक्स दरों का उल्लेख निम्न है :

किफायती मकानों के निर्माण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 1 प्रतिशत की नई दर निम्नलिखित के लिए उपलब्ध रहेगी:

ए) ऐसे सभी मकान जो जीएसटीसी द्वारा तय की गई किफायती घरों की परिभाषा पर खरे उतरते हैं (गैर-महानगर में क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर/महानगरों में क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर और कीमत 45 लाख रुपये तक)।

बी) वर्तमान केन्द्रीय एवं राज्य आवास योजनाओं के तहत मौजूदा परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसे निर्माणाधीन किफायती मकान जो 8 प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर के लिए पात्र हैं (एक तिहाई भूमि एबेटमेंट के बाद)।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5 प्रतिशत की नई दर निम्नलिखित के निर्माण पर लागू होगी :

ए) मौजूदा परियोजनाओं में किफायती घरों को छोड़ अन्य सभी मकान, चाहे इनकी बुकिंग 1 अप्रैल, 2019 से पहले या उसके बाद हुई हो। 1 अप्रैल, 2019 से पहले बुक किए गए मकानों के मामले में नई दर 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद देय किस्तों पर लागू होगी।

बी) नई परियोजनाओं के तहत किफायती घरों को छोड़ अन्य सभी मकान।

सी) आवासीय अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) परियोजना (आरआरईपी) के तहत दुकानों एवं कार्यालय जैसे सभी वाणिज्यिक अपार्टमेंट जिनका कुल कारपेट एरिया समस्त अपार्टमेंट के समग्र कारपेट एरिया के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। ■

पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 2 करोड़ से अधिक लघु/सीमांत किसानों को लाभ मिला

देश भर के सभी छोटे और सीमांत भूमिधारक किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हें कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 01 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा निधि (पीएम-किसान) नामक एक नई योजना की शुरुआत की। कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले किसानों के परिवारों को प्रति वर्ष 6,000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा।

यह 6,000/- रुपया चार महीने के अंतराल पर 2,000/- रुपये की तीन किश्तों में पूरे वर्ष के दौरान दिया जाएगा। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 31 मार्च 2019 को समाप्त 4 महीने की अवधि के लिए जारी की जा रही है। इस योजना से देश भर के करीब 12.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

इस योजना को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में किया गया था। पहले 4 महीने की अवधि की 2000 रुपये की पहली किस्त करीब 1.01 करोड़ किसानों को जारी किए गए थे, जिस पर करीब 2021 करोड़ रुपये का खर्च आया।

इस योजना को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है और पहली किस्त जारी की जा चुकी है। अब तक करीब 2 करोड़ से भी अधिक लघु और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। दरअसल, यह एक सतत चलने वाली योजना है और विभाग का उद्देश्य सभी पात्र लघु और सीमांत किसान परिवारों को इसके अंतर्गत लाना है। ■

अप्रैल-फरवरी, 2018-19 के दौरान निर्यात में 8.73 प्रतिशत का इजाफा

भारत से अप्रैल-फरवरी, 2018-19 में 483.98 अरब अमेरिकी डॉलर का समग्र निर्यात (वाणिज्यिक एवं सेवाएं) होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.73 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह अप्रैल-फरवरी, 2018-19 के दौरान 577.31 अरब अमेरिकी डॉलर का समग्र आयात होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

फरवरी, 2019 में 26.67 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ जो फरवरी 2018 में हुए निर्यात की तुलना में 2.44 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि को दर्शाता है। रुपये के लिहाज से फरवरी, 2019 में निर्यात 1,89,931.49 करोड़ रुपये का हुआ जो फरवरी, 2018 के मुकाबले 13.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी को रेखांकित करता है।

फरवरी, 2019 में जिन प्रमुख जिंस समूहों के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

अप्रैल-फरवरी, 2018-19 के दौरान कुल निर्यात 289.47 अरब अमेरिकी डॉलर (20,88,290.52 करोड़ रुपये) का हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में डॉलर के लिहाज से 8.85 प्रतिशत और रुपये के लिहाज से 18.26 प्रतिशत अधिक है।

फरवरी, 2019 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न व जेवरात निर्यात 19.87 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ, जो फरवरी, 2018 की तुलना में 5.14 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह अप्रैल-फरवरी, 2018-19 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न व जेवरात निर्यात 217.43 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ, जो अप्रैल-फरवरी, 2017-18 की तुलना में 7.66 प्रतिशत अधिक है। ■

अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयला उत्पादन में 8.0% की वृद्धि

अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयले का उत्पादन 638.46 मिलियन टन (एमटी) रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 591.42 एमटी कोयले का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर 8.0% की वृद्धि दर्ज हुई।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का वर्ष 2018-19 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य 610.00 एमटी निर्धारित किया गया था। अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयले का उत्पादन 527.70 एमटी रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 495.08 एमटी रहा था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि दर 6.6% रही।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) का वर्ष 2018-19 के लिए कोयले का उत्पादन लक्ष्य 65.00 एमटी निर्धारित किया गया था। अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयले का उत्पादन 57.94 एमटी रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 54.64 एमटी रहा था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर 6.0% की वृद्धि दर दर्ज हुई।

आबद्ध खानों का कोयला उत्पादन लक्ष्य वर्ष 2018-19 के लिए 40.00 एमटी निर्धारित किया गया था। अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयले का उत्पादन 44.41 एमटी रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 33.76 एमटी कोयला का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर 31.6% की वृद्धि दर दर्ज हुई। इस प्रकार आबद्ध खानों ने फरवरी 2019 तक अपने कोयले का उत्पादन लक्ष्य (40.00 एमटी) पहले ही अर्जित कर लिया।

2018-19 के लिए अन्य खानों का कोयला उत्पादन लक्ष्य 15.00 एमटी निर्धारित किया गया था। अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान इन खानों का कोयला उत्पादन 8.40 एमटी था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.94 एमटी कोयले का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर 5.8% की वृद्धि दर प्राप्त हुई।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का महीनेवार कोयला उत्पादन निम्न है :

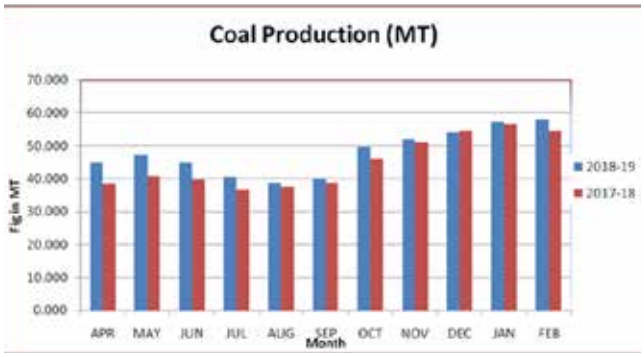

भारतीय वायुसेना में चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल

भारतीय वायुसेना ने 25 मार्च को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से सीएच 47 एफ (I) चिनूक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल बी एस धनोआ समारोह के विशिष्ट अतिथि थे।

दरअसल, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2015 में 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों के लिए मेसर्स बोइंग लिमिटेड के साथ समझौता किया था। चार हेलीकॉप्टरों की पहली खेप समय पर उपलब्ध करा दी गयी थी। अंतिम खेप अगले वर्ष मार्च तक पहुंच जाएगी। इन हेलीकॉप्टरों को भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। ■

मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 14 मार्च को राजस्थान के रेगिस्तान रेंज में दूसरी बार देश में विकसित कम वजन का फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एमपीएटीजीएम) का सफल परीक्षण किया। एमपीएटीजीएम में एकीकृत वैमानिकी व्यवस्था के साथ अत्याधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड रडार (आईआईआर) साधक है। पहला परीक्षण 13 मार्च, 2019 को किया गया था। दोनों मिशनों में मिसाइलों ने विभिन्न रेंजों पर निर्धारित लक्ष्यों पर निशाना साधा। मिशन के सारे उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं। ■

जनसंघ ही क्यों?

दीनदयाल उपाध्याय

अपना देश आज अत्यधिक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। राष्ट्र जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं और न समाज का ही कोई ऐसा वर्ग है, जिसे आज अनपेक्षित रूप से कठोरतम समस्याओं का सामना न करना पड़ रहा हो। स्वाधीनता के प्रथम झोंके में स्वतंत्रता संग्राम के समय जगाई गई समस्त आशाओं पर तुषारपात हो गया है। भ्रम के बादल अवश्य बंट गए हैं, पर इससे न वास्तविकता का ज्ञान हो पाया है और न संकट का सामना करने की दृढ़ता ही जगी है। इसके विपरीत इससे चारों ओर किंकर्तव्यविमूढ़ता एवं अविश्वास का वातावरण निर्मित हो गया है। जनता का अपने नेताओं पर से विश्वास उठ गया है। वह न तो उसके द्वारा संचालित नीतियों पर ही आस्था रखती है, न उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर।

अपने समय की सर्वप्रमुख आवश्यकता उस विश्वास को पुनः प्रतिष्ठित करने की है। यह प्रश्न चीनी आक्रमण या आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रश्नों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके बिना हम कोई भी समस्या हल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए कुछ वास्तविक विचार करने एवं क्रांतिकारी क़दम उठाने की आवश्यकता है।

चारों ओर का यह वातावरण कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह तो कांग्रेस नेतृत्व द्वारा निरंतर अपनाई गई नीतियों एवं कार्यों का निश्चित परिणाम है। जनता को सबसे जबरदस्त धक्का उस दिन लगा, जिस दिन देश का विभाजन हो गया। भारत माता की मूर्ति खंडित हो गई और हम देखते रहे।

इससे मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा समाप्त हो गई और राष्ट्रीयता की जड़ पर ही कुठाराघात हो गया। भारत की स्वतंत्रता, राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण के अतिरिक्त और कुछ भी न रही। कोई सैद्धांतिक अधिष्ठान न होने के कारण उससे जनता या राजकर्ताओं में निस्स्वार्थ सेवा एवं अधिकाधिक बलिदान की प्रेरणा का संचार न हो सका। इसने केवल भारत की एकता एवं सुदृढ़ता को ही नष्ट नहीं किया तो भारत की प्राचीन संस्कृति एवं परंपरा के प्रति आस्था को भी डिगा दिया। सरकार ने भी जनता के सम्मुख समाजवाद एवं सेक्युलरवाद का ही प्रतिपादन किया। पर वे नारे मात्र रह गए। जनता में कोई उत्साह संचारित न कर सके। इसके विपरीत उन्होंने ऐसी वृत्तियों को जन्म दिया, जो त्याग, पवित्रता एवं सेवा के स्थान पर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा एवं अकर्मण्यता को ही बढ़ावा देने में सफल हुए। इसने उन्हें भावात्मक रूप से संगठित करने के स्थान पर सांप्रदायिकता, जातीयता और विघटनवादिता का ही शिकार बनाया।

ये सब बातें केवल संवैधानिक परिवर्तनों से ठीक नहीं हो सकती थीं। श्री जयप्रकाश नारायण तथा अन्य सर्वोदयवादी नेता इस प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही विचारक हैं, जो केंद्र में मिली-जुली सरकार बनाकर राष्ट्रीय ऐक्ट प्रस्थापित करने की बातें करते हैं। अधिक अधिकार प्रदान कर लोगों में उत्साह का संचार करने के लिए विकेंद्रीकरण के क़ानून बनाए जा रहे हैं। पर इसकी सफलता में भी संदेह है। इससे तो केवल भ्रष्टाचार एवं गुटबंदी का ही विकेंद्रीकरण होगा। परिवर्तन तो सिद्धांत की ठोस भूमिका पर आधारित होना चाहिए।

डॉ. संपूर्णानंद' ने एक विचार गोष्ठी में इसी तथ्य को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है, 'वर्किंग कमेटी' ने पहले दिन तिब्बत के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया है। उक्त प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातों का संदर्भ दिया गया है, जो अनादि काल से हमें प्राप्त हुई हैं और जो हमारी चेतना का एक आवश्यक अंग बन गई हैं। यह संदर्भ उत्साहवर्धक था। मैं समझता हूं कि यदि हम राष्ट्र के नाम अपनी अपील को उन मूलभूत तथ्यों के ऊपर आधारित करें, जिन पर हमारा जीवन संबंधी दृष्टिकोण आधारित है तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। जनता को वह प्रेरणा प्राप्त होगी, जिसकी आज आवश्यकता है। जनता के सम्मुख कोई ऐसी बात रहनी चाहिए, जिसके लिए वे जीने के लिए तत्पर हो, उसे पाने के लिए उत्कंठित हो और यदि आवश्यकता पड़े तो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो। जनता की साधारण भाषा में इसे धर्म कहा जाता है। जब तक हमारे समस्त कार्यकलापों का, चाहे वे सामाजिक हों अथवा व्यक्तिगत, आधार धर्म नहीं होता, मनुष्य की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन अथवा समाज की आवश्यकता एवं व्यक्ति की आकांक्षा के बीच कोई सामंजस्य बिठाना संभव नहीं होगा।

भारत में सत्ताधारी या विरोधी दलों ने भारतीय जीवन के इस मूलभूत तथ्य की ओर दुर्लक्ष्य किया है। इसी कारण भारतीय जनसंघ को अवतरित होना पड़ा। इस देश को आधुनिकता प्रदान करने के फेर में उन लोगों ने प्राचीन मूल्यों को समाप्त कर देश को शक्तिहीन बना डाला है। सुधार के नाम पर उन्होंने लोगों को एवं स्वयं अपने आपको भी भ्रमित किया है। महर्षि दयानंद एवं महात्मा गांधी भी महान् सुधारक थे। वे कोई सामाजिक कुरीति को सहन नहीं करते थे, पर उन्होंने न तो धर्म की उपेक्षा की और न उसके महत्त्व से इनकार ही किया। इसके विपरीत उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों से अपील की और उन्हें सफलता मिली। साधारण जनता की निगाहों में स्वधर्म को अलग नहीं किया जा सकता।

देश की अखंडता, राष्ट्रीयता एवं सांस्कृतिक एकता, यही हमारे राष्ट्रधर्म की आधारशिला है। यही वह आधार है, जिस पर खड़े होकर हमने संगठित रूप से अंग्रेजों का सामना किया। यह एकता बाहरी विभिन्नताओं के होते हुए भी हमारे समस्त इतिहास, जीवन और साहित्य के नस-नस में प्रवाहित होती रही। इसी श्रद्धा के कारण जनसंघ ने कश्मीर के विभाजन का अथवा वहां और शेष भारत के लोगों के बीच न्याय प्राप्ति या मताधिकार के संबंध में होनेवाले भेदभाव का विरोध किया। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता

एवं आदर की परंपरागत भावना के कारण हम प्रत्येक व्यक्ति की उपासना पद्धति एवं विश्वासों की स्वतंत्रता के हामी हैं, पर साथ ही राजनीति में किसी व्यक्ति के धर्म को जबरदस्ती लादने का विरोध करते हैं। राजनीति में हम धर्म के आधार पर अल्पमत या बहुमत को भी मान्य नहीं करते। हम चाहते हैं कि ईसाई एवं मुसलमान अपनी पृथकतावादी नीति त्यागकर अविभाज्य अंग बनें। नौकरी, भाषा, प्रशासकीय नियुक्तियां तथा चुनाव आदि में अल्पमतों के अधिकारों के नाम पर विशेषाधिकार की मांग पर जोर देना यह 'एक राष्ट्र' के सिद्धांत के प्रतिकूल है। उनकी दुराग्रही मांगों को मानकर कांग्रेस अपने पार्टी के हित के लिए राष्ट्रीय एकता के मार्ग में रोड़े अटका रही है। स्वधर्मानुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी को भी अधिक लाभप्रद नौकरी न दी जाए।

'सभी को काम' यही हमारी आर्थिक रचना का आधार होना चाहिए। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि हम विदेशी औद्योगीकरण के तरीक़ों का अंधानुकरण नहीं कर सकते। छोटी मशीनों द्वारा संचालित कुटीर उद्योग ही हमारे लिए अनुकूल हो सकते हैं। उत्पादक वस्तुओं का निर्माण बड़े-बड़े कारख़ानों में किया जा सकता है।

समाजवाद एवं पूंजीवाद दोनों ही विदेशी विचारधाराएं हैं। जनसंघ दोनों को अस्वीकार करता है। जब हम विशाल साहसिक योजनाओं को अंगीकार करते हैं, तभी ये प्रश्न कुछ महत्त्व रखते हैं। पर जब हमारा औद्योगिक ढांचा विकेंद्रित, पारिवारिक स्तर पर स्वयं संचालित अथवा सहकारी तरीक़ का होगा, तब यह सामाजिक संबंधों पर कोई विशेष असर नहीं डालेगा। ऐसी अवस्था में अधिकांश उद्योगों का संचालन राज्य के उचित नियंत्रण एवं निरीक्षण में व्यक्तिगत आधार पर होना चाहिए। राज्य ऐसे उद्योगों को अवश्य संचालित करे, जो व्यक्तिगत क्षेत्रों द्वारा संभव न हों या जिनका व्यक्तिगत क्षेत्रों द्वारा संचालन राज्य की सुरक्षा के हित में न हो। भारतीय समाज रचना में प्रारंभिक इकाई के रूप में परिवार का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। यदि इसे केवल उपभोग की ही नहीं उत्पादन की भी इकाई बनाया जा सके तो इसे पुनः वही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सकता है। संगठित पारिवारिक जीवन में भारतीय संस्कृति के मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा भी संभव हो सकेगी।

मैं यहां जनसंघ के कार्यक्रमों की गहराई में नहीं जाना चाहता। उसका सहकारी कृषि का विरोध और देश की परिस्थिति का वास्तविक आकलन किए बगैर तथा अपनी सुविधाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिनायकवादी तरीके से की गई सरकारी योजनाओं से सहमत न होना, सभी को ज्ञात है। राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं एकता के मूल्य पर पाकिस्तान एवं चीन के प्रति अपनाई जाने वाली तुष्टीकरण की नीति के हम प्रबल विरोधी हैं यह दोहराना अनावश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उन आदर्शों के प्रति अपनी आस्था दृढ़ करें, जिसे अनेक युगों से जनता ने संजोकर रखा है। केवल ये आदर्श ही जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। दूसरी आवश्यक बात यह है कि लोग अपने दल में आस्था रखें। असंतुष्ट होकर या दूसरों के साथ मिलकर बनने वाले नए दलों का कुछ लोग भले ही स्वागत करते हों, पर इससे जनता में भ्रम उत्पन्न होता है। नेता अपने कार्य के औचित्य को सिद्ध करने में असमर्थ रहते हैं। अभी हो रहे उच्चस्तरीय समझौते मज़बूत नींव पर आधारित नहीं हैं। सर्वदलीय मोरचे अथवा मिली-जुली सरकार राजनीतिक क्षेत्र में अधिकाधिक अव्यवस्था ही उत्पन्न करेगी। इससे जनता का प्रशिक्षण न हो सकने के कारण जनतंत्र को बाधा पहुंचेगी।

सिद्धांत, नीति एवं कार्यक्रमों के अतिरिक्त जनता के लिए दल के व्यक्तियों का भी अलग महत्त्व होता है। कांग्रेस की नीतियों अथवा सिद्धांतों के कारण नहीं, तो कुछ लोगों के ग़लत व्यवहार के कारण आज कांग्रेस बदनाम हो रही है। निराशा के गहन अंधकार में भटकती हुई जनता आज यह समझने को बाध्य हो गई है कि जिन्हें उसने भगवान् समझकर पूजा की, वे निरे 'पत्थर के देवता' निकले। सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर से उनका विश्वास उठ गया है। जनसंघ को इस विश्वास को पुनः प्रस्थापित करना है। हमारे कार्यकर्ताओं की अपने कार्य के प्रति अटूट श्रद्धा एवं सिद्धांतप्रियता ही यह चमत्कार कर सकती है। अतः संगठन के संख्या बल को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी जनसंघ अपने कार्यकर्ताओं की योग्यता के विकास पर ही अधिक बल देना चाहता है। अनुशासित दल ही अनुशासित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।

राष्ट्र के सम्मुख अनेक कठिन प्रश्न उपस्थित हैं। साथ ही, अनेक गंभीर संकट देश के भाग्याकाश में मंडरा रहे हैं। पर उन पर विजय प्राप्त करने का कोई सरल मार्ग नहीं हो सकता। राजनीतिक समझौता या व्यवस्थाओं से चुनावों में विजय प्राप्त की जा सकती है। अनेक प्रदेशों एवं केंद्र में भी कांग्रेस को हराया जा सकता है, परंतु इससे तब तक कोई अच्छे परिणाम नहीं निकल सकेंगे, जब तक नए आने वाले शासक जनता को प्रेरणा दे सकने योग्य राष्ट्रीय चैतन्ययुक्त ऐसे कार्यक्रम एवं सिद्धांत प्रस्तुत न करें, जो स्वयं उनके आचरण में प्रकट होते हों।

भारतीय जनसंघ वर्तमान संकट का इसी विधायक तरीके से सामना करना चाहता है और जैसा समर्थन जनता द्वारा इसे प्राप्त हो रहा है। उससे यदि इसका यह लंबा दिखने वाला मार्ग ही कहीं सबसे सरल मार्ग सिद्ध हो जाए तो किसी को आश्चर्य न होना चाहिए। ■

(-पाञ्चजन्य, जनवरी 15, 1960)

समाजवाद एवं पूंजीवाद दोनों ही विदेशी विचारधाराएं हैं। जनसंघ दोनों को अस्वीकार करता है। जब हम विशाल साहसिक योजनाओं को अंगीकार करते हैं, तभी ये प्रश्न कुछ महत्त्व रखते हैं। पर जब हमारा औद्योगिक ढांचा विकेंद्रित, पारिवारिक स्तर पर स्वयं संचालित अथवा सहकारी तरीक़ का होगा, तब यह सामाजिक संबंधों पर कोई विशेष असर नहीं डालेगा।

नहीं रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर

(13 दिसंबर, 1955 - 17 मार्च, 2019)

गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर का 17 मार्च को उनके पणजी स्थित निजी आवास पर निधन हो गया। वह 63 वर्ष के थे। चार बार के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री श्री पर्रिकर फरवरी 2018 से ही अग्नाशय संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और उनका स्वास्थ्य दो दिन पहले बहुत बिगड़ गया था। श्री पर्रिकर के परिवार में दो पुत्र और उनका परिवार है।

13 दिसंबर, 1955 को गोवा के मापुसा में जन्मे श्री पर्रिकर की शिक्षा लोयोला स्कूल, मडगांव में हुई और उसके बाद उन्होंने 1978 में स्नातक की उपाधि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले श्री पर्रिकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। वे युवा अवस्था में ही शिक्षा के अंतिम वर्षों में एक मुख्य शिक्षक (मुख्य प्रशिक्षक) बन गए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक होने के बाद उन्होंने मापुसा में आरएसएस का काम फिर से शुरू किया और 26 साल की उम्र में संघचालक बन गए।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में श्री पर्रिकर को 1994 में गोवा विधान सभा के लिए चुने गये। वे 24 अक्टूबर, 2000 को पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने और 27 फरवरी, 2002 तक बने रहे। उसके बाद 3 जून, 2002 को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और 2 फरवरी, 2005 तक सेवा की। वे 9 मार्च, 2012 को तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने और 8 नवंबर, 2014 तक इस पद पर रहे। 9 नवंबर, 2014 को श्री पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री बने और 13 मार्च, 2017 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने 14 मार्च, 2017 को फिर से गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

श्री पर्रिकर को 2001 में आईआईटी, मुंबई द्वारा 'प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार', 2018 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा द्वारा मानद डॉक्टरेट और 2018 में डॉ. एस.पी. मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ■

शोक संदेश

मैं गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर परिकर के निधन का समाचार पाकर अत्यंत दुखी हूं। वे साहस और सहनशीलता के साथ बीमारी का सामना करते हुए दिवंगत हो गए। श्री परिकर समर्पण और सत्यनिष्ठा के प्रतीक थे और उन्होंने आजीवन जनता की सेवा की। राष्ट्र और गोवा के लोगों की उन्होंने जो सेवा की, उसको भुलाया नहीं जा सकता।

रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति

श्री परिकर देश के अत्यंत लोकप्रिय और ईमानदार वरिष्ठ राजनेता थे। वे एक जुझारू और समर्पित व्यक्ति थे, जिन्होंने मूल्यों और सिद्धांतों से परिपूर्ण जीवन जिया। गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर परिकर के असामयिक निधन का समाचार सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है। वे देश के अत्यंत लोकप्रिय और ईमानदार वरिष्ठ राजनेता थे। वे एक जुझारू और समर्पित व्यक्ति थे, जिन्होंने मूल्यों और सिद्धांतों से परिपूर्ण जीवन जिया। राष्ट्र और गोवा ने अपना अत्यंत योग्य पुत्र खो दिया है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं।

एम. वैंकेया नायडू, उपराष्ट्रपति

श्री मनोहर परिकर बेजोड़ नेता थे। एक सच्चे देशभक्त और असाधारण प्रशासक, सब उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा की, जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। मैं उनके निधन से बहुत दुःखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम् शांति।

श्री मनोहर परिकर आधुनिक गोवा के निर्माता थे। अपने मिलनसार और सौम्य व्यक्तित्व के कारण वे वर्षों तक राज्य के लोकप्रिय नेता बने रहे। उनकी जन नीतियों के कारण गोवा ने विकास की ऊंचाईयां तय की। रक्षा मंत्री के रूप में श्री मनोहर परिकर के कार्यों के प्रति देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। जब वे रक्षा मंत्री थे तब देश ने ऐसे तमाम निर्णय किये थे, जिनसे भारत की क्षमताओं में इजाफा हुआ था, स्वदेशी रक्षा उत्पादन में बढ़ोत्तरी आई थी और पूर्व सैनिकों का जीवन बेहतर हुआ था।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारत ने एक सच्चा देशभक्त खो दिया जिसका पूरा जीवन राष्ट्र और सिद्धांतों को समर्पित था। परिकर ने दिखाया कि कैसे भाजपा का एक कार्यकर्ता उसके सबसे कठिन समय में भी, राष्ट्र सर्वप्रथम, फिर पार्टी और स्वयं को अंत में रखने के सिद्धांत पर अटल रहता है। मनोहर परिकर का निधन बेहद दुःखदायी है। उनके रूप में भारत ने एक सच्चा देशभक्त खोया है जिसने निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन देश और सिद्धांतों के हवाले कर दिया। जनता के प्रति परिकर का समर्पण और उनका कर्तव्य अनुकरणीय है। भारत के रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पूरी भाजपा परिकर के परिवार के साथ है। भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं और खास तौर से गोवा के लोगों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। गोवा के लोग उनके परिवार जैसे थे। ईश्वर उनके परिवार को यह आघात सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति।

अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

निःशब्द हूं। सुशील और सादगीपूर्ण राजनीति का चेहरा आज खो गया। मनोहर भाई सही मायने में हर कार्यकर्ता के हृदय पर राज करने वाले नेता थे। राजनीति में शुरुआती दिनों से वे मेरे साथी और अच्छे मित्र थे। गोवा के विकास के लिए लिए आख़िरी सांस तक संघर्ष करने वाले भारत मां के इस महान सपूत को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि।ॐ

नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

परिकर निष्कपट, ईमानदार और संवेदनशील राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वह सरल और जमीन से जुड़े थे, मैंने परिकर से बहुत कुछ सीखा है। रक्षा मंत्री के तौर पर सशस्त्र बलों को आधुनिक और ताकतवर बनाने में उनका योगदान अद्वितीय है।

निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री

मेरे अच्छे मित्र मनोहर परिकर के असमय निधन से मैं बेहद दुःखी हूं। वह सत्यनिष्ठा की मिसाल थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले आईआईटीयन थे। भारत के महान सपूत समय से पहले हमें छोड़कर चले गए। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे मेरे प्रिय दोस्त।

सुरेश प्रभु, केंद्रीय मंत्री

गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर परिकर के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। आज मां भारती ने अपना एक सच्चा सपूत खो दिया है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं।

शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा बांग्लादेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने 11 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त रूप से बांग्लादेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए ई-पट्टिका का अनावरण किया। दोनों नेताओं ने बसों और ट्रकों की आपूर्ति, 36 सामुदायिक क्लीनिकों के उद्घाटन, 11 जल उपचार संयंत्रों और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के विस्तार के लिए ई-पट्टिका का अनावरण किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना के साथ उनका छठा वीडियो कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत संपर्क के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना का दृष्टिकोण सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि आज के इस अनावरण से न केवल परिवहन कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि ज्ञान कनेक्टिविटी को भी बल मिलेगा।

श्री मादी ने कहा कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बांग्लादेश, भारत और दुनिया के अनुसंधान संस्थानों को आपस में जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि बसें और ट्रक किफायती सार्वजनिक परिवहन में मददगार होंगे; जल उपचार संयंत्र स्वच्छ पानी की आपूर्ति में मदद करेंगे और सामुदायिक क्लीनिक बांग्लादेश में लगभग 2 लाख लोगों को लाभान्वित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं दर्शाती हैं कि भारत-बांग्लादेश संबंध लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बांग्लादेश के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों की सराहना की और भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध निरंतर आगे बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ यह मेरी छठी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इतनी सरलता से और इतनी बार किन्हीं दो देशों के नेतृत्व के बीच में संपर्क होना अपने आप में दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने गहरे और मजबूत हैं।

उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की बात जब भी होती है, तो उसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के विज़न को मानता हूं और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने न सिर्फ़ परिवहन, बल्कि साथ ही नॉलेज में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के क़दम उठाए हैं।

श्री मोदी ने ट्वीट किया कि बांग्लादेश से जुड़कर, भारत का राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क अब बांग्लादेश के स्कॉलर्स और रिसर्च संस्थानों को भारत और पूरे विश्व से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनेगा। बसों और ट्रकों की आपूर्ति बांग्लादेश सरकार द्वारा किफायती सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमिका अदा करेगी।

ट्वीट में श्री मोदी ने लिखा कि जल उपचार संयंत्र हज़ारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे और सामुदायिक क्लीनिक से लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें अपने घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

यह सभी प्रोजेक्ट्स सीधे रूप से जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। यह प्रोजेक्ट्स दर्शाते हैं कि भारत-बांग्लादेश संबंध दोनों देशों की जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं।

उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारत और बांग्लादेश के लोगों के संबंध आत्मीयता और पारिवारिक भावनाओं से परिपूर्ण संबंध हैं। बांग्लादेश का विकास भारत के लिए ख़ुशी का विषय तो है ही, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के विकास के लिए महत्वकांक्षी लक्ष्य तय किये हैं।

ट्वीट में श्री मोदी ने लिखा कि आज मुझे बांग्लादेश से यहां आए कई युवा सांसदों और नेताओं से मिलने का अवसर मिला। उनकी प्रतिभा और कर्मठता में मैं भारत-बांग्लादेश संबंधों का उज्जवल भविष्य देखता हूं। ■

डॉ. लोहिया की याद में...

नरेन्द्र मोदी

आज का दिन देश के महान क्रांतिकारियों के सम्मान का दिन है। मां भारती के अमर सपूतों वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हैं। इसके साथ ही अद्वितीय विचारक, क्रांतिकारी तथा अप्रतिम देशभक्त डॉ. राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर सादर नमन। प्रखर बुद्धि के धनी डॉ. लोहिया में जन सरोकार की राजनीति के प्रति गहरी आस्था थी।

जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब युवा लोहिया ने आंदोलन की कमान संभाली और डटे रहे। उन्होंने भूमिगत रहते हुए अंडरग्राउंड रेडियो सेवा शुरू की, ताकि आंदोलन की गति धीमी न पड़े। गोवा मुक्ति आंदोलन के इतिहास में डॉ. लोहिया का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जहां कहीं भी गरीबों, शोषितों, वंचितों को मदद की जरूरत पड़ती, वहां डॉ. लोहिया मौजूद होते थे।

डॉ. लोहिया के विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने कृषि को आधुनिक बनाने तथा अन्नदाताओं के सशक्तीकरण को लेकर काफी कुछ लिखा। उनके इन्हीं विचारों के अनुरूप एनडीए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि सिंचाई योजना, e-Nam, सॉयल हेल्थ कार्ड और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों के हित में काम कर रही है।

डॉ. लोहिया समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था और महिलाओं एवं पुरुषों के बीच की असमानता को देखकर बेहद दुःखी होते थे। 'सबका साथ, सबका विकास' का हमारा मंत्र तथा पिछले पांच सालों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यह दिखाता है कि हमने डॉ. लोहिया के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अगर आज वे होते तो एनडीए सरकार के कार्यों को देखकर निश्चित रूप से उन्हें गर्व की अनुभूति होती।

जब कभी भी डॉ. लोहिया संसद के भीतर या बाहर बोलते थे, तो कांग्रेस में इसका भय साफ नजर आता था। देश के लिए कांग्रेस कितनी घातक हो चुकी है, इसे डॉ. लोहिया भलीभांति समझते थे। 1962 में उन्होंने कहा था, "कांग्रेस शासन में कृषि हो या उद्योग या फिर सेना, किसी भी क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है।"

उनके ये शब्द कांग्रेस की बाद की सरकारों पर भी अक्षरशः लागू होते रहे। बाद के कांग्रेस शासनकालों में भी किसानों को परेशान किया गया, उद्योगों को हतोत्साहित किया गया (सिर्फ कांग्रेस नेताओं के दोस्तों और रिश्तेदारों के उद्योगों को छोड़कर) और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी की गई।

कांग्रेसवाद का विरोध डॉ. लोहिया के हृदय में रचा-बसा था। उनके प्रयासों की वजह से ही 1967 के आम चुनावों में सर्वसाधन संपन्न और ताकतवर कांग्रेस को करारा झटका लगा था। उस समय अटल जी ने कहा था - डॉ. लोहिया की कोशिशों का ही परिणाम है कि हावड़ा-अमृतसर मेल से पूरी यात्रा बिना किसी कांग्रेस शासित राज्य से गुजरे की जा सकती है।

दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति में आज ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर डॉ. लोहिया भी विचलित, व्यथित हो जाते। वे दल जो डॉ. लोहिया को अपना आदर्श बताते हुए नहीं थकते, उन्होंने पूरी तरह से उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी है। यहां तक कि ये दल डॉ. लोहिया को अपमानित करने का कोई भी कोई मौका नहीं छोड़ते।

ओडिशा के वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने कहा था, "डॉ. लोहिया अंग्रेजों के शासनकाल में जितनी बार जेल गए, उससे कहीं अधिक बार उन्हें कांग्रेस की सरकारों ने जेल भेजा।" आज उसी कांग्रेस के साथ तथाकथित लोहियावादी पार्टियां अवसरवादी महामिलावटी गठबंधन बनाने को बेचैन हैं। यह विडंबना हास्यास्पद भी है और निंदनीय भी है।

डॉ. लोहिया वंशवादी राजनीति को हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक मानते थे। आज वे यह देखकर जरूर हैरान-परेशान होते कि उनके 'अनुयायी' के लिए अपने परिवारों के हित देशहित से ऊपर हैं। डॉ. लोहिया का मानना था कि जो व्यक्ति 'समता' 'समानता' और 'समत्व भाव' से कार्य करता है, वह योगी है। दुःख की बात है कि स्वयं को लोहियावादी कहने वाली पार्टियों ने इस सिद्धांत को भुला दिया। वे 'सत्ता', 'स्वार्थ' और 'शोषण' में विश्वास करती हैं।

इन पार्टियों को जैसे तैसे सत्ता हथियाने, जनता की धन-संपत्ति को लूटने और शोषण में महारत हासिल है। गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित समुदाय के लोगों के साथ ही महिलाएं इनके शासन में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करतीं, क्योंकि ये पार्टियां अपराधी और असामाजिक तत्त्वों को खुली छूट देने का काम करती हैं।

डॉ. लोहिया जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी के पक्षधर रहे, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आकंठ डूबी पार्टियों का आचरण इससे अलग रहा। यही वजह है कि तथाकथित लोहियावादी पार्टियों ने तीन तलाक की अमानवीय प्रथा को खत्म करने के एनडीए सरकार के प्रयास का विरोध किया। इन पार्टियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इनके लिए डॉ. लोहिया के विचार और आदर्श बड़े हैं या फिर वोट बैंक की राजनीति?

आज 130 करोड़ भारतीयों के सामने यह सवाल मुंह बाए खड़ा है कि- जिन लोगों ने डॉ. लोहिया तक से विश्वासघात किया, उनसे हम देश सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जाहिर है, जिन लोगों ने डॉ. लोहिया के सिद्धांतों से छल किया है, वे लोग हमेशा की तरह देशवासियों से भी छल करेंगे। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

अपना टाइम आ गया है और ये समय है आपके पास के वोटिंग सेंटर पर जोश हाई करने का: नरेन्द्र मोदी

लोक सभा चुनाव 2019 के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीटर पर विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 100 जानी-मानी हस्तियों से पूरे उत्साह के साथ मतदान करने और इस हेतु लोगों को प्रेरित करने की अपील की और उन्हें टैग किया। इसमें श्री राहुल गांधी, सुश्री ममता बनर्जी, श्री शरद पवार, श्री नीतीश कुमार, श्री सचिन तेंदुलकर, सुश्री गीता फोगाट, सुश्री बबीता फोगाट, जाने-माने पत्रकार, फिल्मी हस्तियां और अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मोदी ने एक ट्वीट में लिखा "मेरे दोस्त रणवीर सिंह, वरुण धवन और विक्की कौशल। कई युवा आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्हें यह बताने का समय आ गया है- अपना टाइम आ गया है और ये समय है आपके पास के वोटिंग सेंटर पर जोश हाई करने का।"

प्रसिद्ध गायिका सुश्री लता मंगेशकर और संगीतकार श्री ए आर रहमान से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपील की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- मैं विनम्रतापूर्वक आप से अनुरोध करता हूं कि वे 2019 के चुनावों में अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। एक वोट लोगों की आवाज सुनने का एक शानदार तरीका है। श्री मोदी ने श्रीमती दीपिका पादुकोण, सुश्री आलिया भट्ट और

श्रीमती अनुष्का शर्मा से भी वोट करने की अपील। श्री मोदी ने श्री अक्षय कुमार, सुश्री भूमि पेडणेकर और श्री आयुष्मान को टैग करते हुए लिखा, 'डियर अक्षय कुमार, भूमि पेडणेकर और आयुष्मान खुराना, एक वोट की शक्ति बहुत होती है, हम सबको इसके महत्व पर जागरुकता बढ़ाने की जरूरत है। थोड़ा दम लगाइए और वोटिंग को एक सुपरहिट कथा बनाइए।'

श्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "वोटिंग ना केवल हमारा अधिकार है बल्कि हमारी ड्यूटी भी है। डियर सलमान खान और आमिर खान अपने अंदाज में ये देश के युवा को मोटिवेट और इंस्पायर करने का समय है। ताकि हम अपना लोकतंत्र और अपना देश मजबूत कर सकें।''

प्रधानमंत्री श्री मोदी की अपील पर सितारों ने पूरे उत्साह के साथ जवाब दिया। श्री अमिताभ बच्चन ने लिखा - आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 90 करोड़ मतदाता, 543 विजेता। हर मत संविधान की श्रेष्ठता के लिए है। संविधान प्रजातंत्र की पवित्र किताब है। 90 करोड़ में से 60 करोड़ से अधिक 35 साल से कम आयु के हैं। नौजवान आने वाले कल के बारे में सवाल पूछते हैं, गुज़रे कल के बारे में नहीं। आने वाले कल के लिए वोट दीजिए।

श्री करण जौहर ने लिखा- आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम एक समुदाय होने के नाते मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समर्पित हैं और सुनिश्चित करेंगे कि मतदान की शक्ति के बारे में लोगों को बताने के लिए हर ज़रूरी कोशिश हो, ताकि हमारा देश मजबूत हो और लोकतांत्रिक बने। जय हिंद।

श्री आमिर ख़ान ने उसी दिन प्रधानमंत्री के आह्वान का जवाब देते हुए लिखा- बिल्कुल सही कहा सर, आदरणीय पीएम। आइए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सभी नागरिकों को शामिल करें। आइए, अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और अपनी आवाज़ सुनवाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करें।

श्री अक्षय कुमार ने लिखा- नरेंद्र मोदी जी आपने सही कहा। किसी प्रजातंत्र की सही पहचान चुनावी प्रक्रिया में इसके लोगों की भागीदारी से होती है। हमारे देश और लोगों के बीच वोटिंग को सुपर हिट प्रेम कथा होना होगा।

श्री अजय देवगन ने लिखा- मैं 2019 के लोक सभा चुनाव में मतदान करूंगा। आपको भी करना चाहिए।

श्री सलमान खान ने लिखा- हम एक प्रजातंत्र हैं और यह हरेक भारतीय का अधिकार है कि वोट करे। मैं हरेक योग्य भारतीय से गुज़ारिश करता हूं कि मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करें और सरकार बनाने में सहयोग करें।

सुश्री आलिया भट्ट ने लिखा- एक वोट देश की आवाज़ होता है। देश का मिज़ाज होता है। अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करिए। अपनी च्वाइस बनाइए।

श्रीमती अनुष्का शर्मा ने लिखा- हमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहए। आइए, एक-दूसरे का हाथ थामें और इस गौरवशाली प्रजातंत्र का जश्न मनाएं। जाइए वोट कीजिए। इस देश और ख़ुद को ताक़तवर बनाइए।

श्री रणवीर सिंह ने लिखा- हमें अपनी महान डेमोक्रेसी का सभी को ज़िम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और वोट के अधिकार का पालन करना चाहिए। देश के नौजवान! वोट करने का वक्त आ गया है।

श्री विक्की कौशल ने लिखा- बिल्कुल सर। हर वोट प्रजातंत्र को बनाने वाले ब्लॉक है। आइए, हममें से हर कोई मतदान सुनिश्चित करके विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र होने का जश्न मनाएं। ■

मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौते की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मार्च को मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दी।

इस समझौते से मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के नियमन तथा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए परस्पर सहयोग में मदद मिलेगी। हस्ताक्षर की तिथि से यह प्रभावी होगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। गौरतलब है कि भारत ने 37 देशों के साथ ऐसी संधियों/सहमति पत्रों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सहमति पत्र की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:-

▸ इस समझौते से दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण संधियों के अनुसार मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों तथा मादक पदार्थों की तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में सहयोग बढ़ेगा।

▸ इस सहमति पत्र के तहत सहयोग में मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में दोनों देशों के राष्ट्रीय विधान के मौजूदा वैधानिक औजारों पर आधारित विवरण का आदान-प्रदान करना, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही तथा अनिवार्य रसायनों, धनशोधन (मनी लॉंडरिंग) के काम में शामिल लोगों की पहचान करने की दृष्टि से नियंत्रित वितरण संचालन के इस्तेमाल में एक दूसरे को अनुमति देना और सहायता देना शामिल हैं।

▸ सहमति पत्र के तहत, इस सहमति पत्र के अनुसार प्राप्त सूचना और दस्तावेजों की गोपनीयता कायम रखने का प्रावधान किया गया है। ■

एजेंडा 2019 - नेतृत्व का मुद्दा

अरुण जेटली

लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। अगले दस सप्ताह विचारों और विचारधाराओं का टकराव, उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व की लड़ाई का गवाह बनेंगे। इन चुनावों में कई मुद्दे प्रासंगिक होगें। आज मैं उन प्रमुख मुद्दों में से एक पर चर्चा करना चाहता हूं जो 2019 के आम चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिकता हैं - नेतृत्व का मुद्दा। पद पर आसीन प्रधानमंत्रियों ने कई बार आम चुनावों का सामना किया है। उनकों सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। सत्ता विरोधी लहर को कुछ यूं परिभाषित किया जा सकता है जब सत्ता से परेशान लोग एक अयोग्य व्यक्ति को वोट देने से भी गुरेज नहीं करते है और परिणामस्वरुप विपक्ष सफल होता है। हालांकि, अगर सत्ता आसीन प्रधानमंत्री का प्रदर्शन, नेतृत्व, नैतिकता और अखंडता को परखा जा चुका हो, तो सत्ता आसीन प्रधानमंत्री भी सफल होते है।

देश ने चौदह साल की अवधि के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी का आकलन किया। वह एक मजबूत नेता बनकर उभरे, उनकी ईमानदारी, राष्ट्रवादी नजरिया और विकास की ललक सबके सामने है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके साथ काम करने वाले लोग जैसाकि सार्वजनिक कार्यालयों में लोगों से अपेक्षित होता है, नैतिकता को अपनाते हैं। उसके खिलाफ एक झूठा और शातिर अभियान चलाया गया। लेकिन इस अभियान के तथ्य हर कानूनी लड़ाई में झूठे ही साबित हुए। उन्होंने इस शत्रुतापूर्ण अभियान को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने राज्य के लिए विकास के लिए अपना स्वयं का एजेंडा रखा और लगातार तीन लोकसभा चुनाव और तीन विधानसभा चुनाव जीते। उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया। वह एक वक्ता के रुप में लोगों के समक्ष है। उन्होंने गुजरात में एक नए नेतृत्व का निर्माण और पोषण किया। पूरी दुनिया में गुजराती आबादी उसके साथ अपनी पहचान करने में गर्व महसूस करती है। उन्होंने उनको प्रेरित किया। उन्होंने 2014 की चुनावी दौड़ में एक ऐसे समय में प्रवेश किया, जब देश ने नेतृत्व का पतन, एक नीतिगत पक्षाघात और अखंडता पर संकट के दौर को देखा। लोगों ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया।

पांच साल बाद कोई राष्ट्र उसका आकलन कैसे करता है?

उन्होंने दुनिया के समक्ष साबित कर दिया कि भारत का प्रशासन ईमानदारी से चलाया जा सकता है। भारत अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और विकास को गति देने के लिए कठोर निर्णय लेने में सक्षम है। आज भारत विश्व में उच्च पटल पर काबिज है। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने एक आर्थिक मॉडल दिया, जहां तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से उभर रहे संसाधनों को बुनियादी ढांचे पर खर्च किया गया साथ ही देश की गरीब जनता तक यह लाभ हस्तांतरित किया गया है। इसमें भी ग्रामीण इलाकों का विशेष ख्याल रखा गया। उन्होंने केवल नारे नहीं दिए, बल्कि गरीबी के स्तर को नीचे लाने के लिए संसाधनों को हस्तांतरित किया और जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। यहां तक कि उनके आलोचक भी उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत के विकास से हतप्रभ हैं।

उन्होंने भारत को एक ऐसे राष्ट्र से आगे विकसित किया है, जो अभी तक केवल खुफिया और सुरक्षा नेटवर्क के माध्यम से आतंक के खिलाफ केवल अपने घर में ही लडाई लड़ रहा था। वहीं वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग कर एक ऐसे राष्ट्र के रूप पहचान दिलवाई जो आतंकवाद को उसके उद्गम पर ही नष्ट करने में सक्षम है। साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता और 2019 के हवाई हमले इस ओर इशारा करते हैं। एनडीए के सहयोगी दलों में नेतृत्व के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं हैं। यह पूर्णतः स्पष्ट है। श्री नरेंद्र मोदी एनडीए का नेतृत्व करते हैं और एनडीए की जीत की स्थिति में वह ही प्रधानमंत्री होंगे। उनका नेतृत्व राष्ट्रीय

स्तर पर स्वीकृत है। उनके नेतृत्व में हुए कार्य खुद बोलते है। आइए हम दूसरी तरफ देखें जहां 'महागठबंधन' का वादा किया जा रहा है, जो कई परस्पर विरोधी गठबंधनों का एक 'गठबंधन' है। यह हमारे प्रतिद्वंद्वियों का एक आत्म-विनाशकारी प्रयास है। बसपा और सपा कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेगी लेकिन अंततः हाथ मिलाएगी। तो क्या तृणमूल और कांग्रेस-पश्चिम बंगाल में गठबंधन करेंगे। ऐसे ही केरल में कांग्रेस और वामपंथी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश की। आज वे प्रतिद्वंद्वी हैं और स्वायत्तता या '1953 से पहले की स्थिति' के खतरनाक एजेंडे पर हैं, लेकिन वह गठबंधन के साथ हाथ मिला सकते हैं। बीजू जनता दल, टीआरएस और वाईएसआरसीपी गठबंधन के साथ नहीं हैं। नेतृत्व का मुद्दा एक निरपेक्ष पहेली है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी एक नामुनासिब नेता हैं। उनकों आजमाया और परखा जा चुका है और वह असफल रहे। मुद्दों को लेकर उनकी समझ में कमी स्पष्ट नजर आती है। वह इस अराजक गठबंधन के नेता बनने की इच्छा रखते हैं। ममता दीदी इस गठबंधन के सूत्रधार के रूप में खुद को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस या वाम दलों के साथ एक भी सीट के लिए समझौता नहीं किया है, लेकिन वह चाहती है कि अगर गठबंधन सफल होता है, तो बाकी दल उनका अनुसरण करें। नीतिगत मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां सहज ही प्रतिकूल होती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा की कद्दावर नेता रहीं मायावती का सफाया हो गया। उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया। वह एक मजबूत बसपा और कमजोर कांग्रेस चाहती है। वह अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। परिणाम घोषित होने के बाद ही वह इसका खुलासा करेंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ 'मजबूरी का गठबंधन' किया है, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी के साथ उसके ऐतिहासिक संघर्ष के दाग नहीं मिटने वाले है। वह एक मजबूत बसपा और कमजोर कांग्रेस चाहती है। लचीली विचारधारा वाले नेता सोचते हैं कि वे सभी के लिए स्वीकार्य हैं। विपक्ष का गठबंधन अस्पष्ट है - यह बिल्कुल कमजोर नजर आता है। चुनावों में अपनी जीत को लेकर कोई भी विपक्षी दल सक्षम दिखाई नहीं देता है। यह गठबंधन स्थिर तो नहीं होगा। इसमें अत्यधिक महत्वाकांक्षी, आत्म-केंद्रित और उस्ताद नेताओं का जमावड़ा है। कांग्रेस और वाम दलों को छोड़ दें, तो ज्यादातर ने अतीत में भाजपा के साथ राजनीतिक गठबंधन किया है। उनकी विचारधारा और गठबंधनों के प्रति उनकी वचनबद्धता व्यापक रूप से भिन्न है। यह लड़ाई एक ऐसे नेता के साथ है जिसके हाथों में देश विकास कर रहा है और सुरक्षित है। उस पर भरोसा किया जा सकता है। वहीं विपक्ष में नेतृत्व की स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही। यहां कई नेता हैं, और सभी एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम पिछले उदाहरणों पर गौर करे तो, वे केवल एक अस्थायी सरकार का वादा कर सकते हैं। एक अराजकता माहौल सुनिश्चित कर सकते है। चयन स्पष्ट है - यह मोदी या अराजकता।

भारत देशभक्त लोगों की भूमि है। हमारे पास वीरता और बलिदान का लंबा इतिहास रहा है। भारत ने आजादी के लिए संघर्ष तो किया, लेकिन उनका सिर हमेशा ऊंचा रहा। हमें अभी भी 1962 के अपने अपमान को पचाना मुश्किल लगता है। हम 1965 और 1971 के युद्धों और 1999 के कारगिल युद्ध को सम्मान और संतुष्टि की भावना से याद करते हैं। भारतीयों का मानना है कि देश को सुरक्षित होना चाहिए। पूरे देश ने एक स्वर में आतंकवाद की निंदा की है, जिसकी कीमत हमें दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और हमारे सुरक्षाकर्मियों एवं नागरिकों के प्राणों के साथ चुकानी पड़ी है।

प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत विकसित करना

पुलवामा में जैश के आतंकवादी हमले ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत देशभक्त लोगों की भूमि है। हमारे पास वीरता और बलिदान का लंबा इतिहास रहा है। भारत ने आजादी के लिए संघर्ष तो किया, लेकिन उनका सिर हमेशा ऊंचा रहा। हमें अभी भी 1962 के अपने अपमान को पचाना मुश्किल लगता है। हम 1965 और 1971 के युद्धों और 1999 के कारगिल युद्ध को सम्मान और संतुष्टि की भावना से याद करते हैं। भारतीयों का मानना है कि देश को सुरक्षित होना चाहिए। पूरे देश ने एक स्वर में आतंकवाद की निंदा की है, जिसकी कीमत हमें दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और हमारे सुरक्षाकर्मियों एवं नागरिकों के प्राणों के साथ चुकानी पड़ी है।

आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई को वोट बैंक से जोड़ने का खतरा

परंपरागत रूप से भारत ने एक स्वर में आतंकवाद और उग्रवाद के किसी भी रूप की निंदा की। जब मुस्लिम समुदाय के एक गुमराह तबके ने अपने मुद्दों को उठाने के लिए विश्व स्तर पर आतंकवाद का सहारा लिया, तो भारतीय मुसलमानों ने मुख्य रूप से उस दर्शन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सौभाग्य से हमारे लिए यह प्रवृत्ति आज तक जारी है। दुर्भाग्य से भारत में कुछ गुमराह करने वाले मॉड्यूल उभर कर सामने आए। वे खतरनाक

हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने उनमें से ज्यादातर को नष्ट कर दिया है।

जब श्री राजीव गांधी सत्ता में थे, तब टाडा को कानूनी मान्यता दी गई थी। इसका उपयोग और दुरुपयोग किया गया, लेकिन यह एक कानून के रूप में जारी रहा। 1993 के मुंबई बम विस्फोट के बाद इसका व्यापक रूप से आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, इसके खिलाफ एक सांप्रदायिक अभियान शुरू किया गया। टाडा को अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया गया। इसके निरस्तीकरण का अभियान शुरू हुआ। नरसिम्हाराव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने टाडा को निरस्त कर दिया। अब भारत जो आतंक से सबसे अधिक प्रभावित था, बिना आतंकवाद विरोधी कानून के था जो एक मजबूत निवारक के रूप में काम करेगा और इसमें आतंक से संबंधित अपराध से निपटने के लिए प्रक्रियात्मक और संवैधानिक दोनों प्रावधान शामिल थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने पोटा कानून को मान्यता दी। इस कानून को मंजूरी देने के लिए सरकार को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा। कांग्रेस ने कानून को निरस्त करने का प्रयास किया। आतंकवाद विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी कानून के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने उस अंतर को कम करने की कोशिश की। इसके बाद से कांग्रेस आतंक पर नरम पड़ने लगी। उसने आतंकवाद के माध्यम से तुष्टिकरण की राजनीति शुरू कर दी।

जब बाटला हाउस मुठभेड़ हुई और आतंकवादी मारे गए, तो कांग्रेस नेताओं ने इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया। उन्होंने दावा किया कि आतंकवादी निर्दोष थे। जब 1993 के मुंबई बम धमाके के दोषी, भारत की वाणिज्यिक राजधानी पर 26/11 हमला करने वाले और संसद हमले के दोषियों को सजा की बात आयी, तो कई कांग्रेसियों ने माफी की अपील करना शुरू कर दिया। इन विघटनकारी शक्तियों ने जो खुद को उदारवादी वामपंथी कहलाना पसंद किया, आतंकवादियों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी।

कांग्रेस की राजनीति में सबसे निचला स्तर देखने को तब मिला जब अलगाववादियों, जेहादियों और माओवादियों से हमदर्दी रखने वाले लोगों ने नई दिल्ली के जेएनयू में 'देश के टुकड़े-टुकड़े' करने के नारे लगाए और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। भारत को टुकड़ों में तोड़ने की बात को अभिव्यक्ति की आजादी करार देने वाली इस घटना ने कांग्रेस के चरित्र को सबके सामने ला दिया। राहुल गांधी चरमपंथियों के साथ नहीं जुड़ने वाली कांग्रेस की विरासत से भटक गए थे। एक बार जब माओवादियों और अलगाववादियों के साथ कांग्रेसियों की पहचान हो गई, तो राहुल गांधी द्वारा शहरी माओवादियों के हितों का समर्थन करना स्वाभाविक था, जो कथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे थे। इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से हमदर्दी रखते हुए कई फैसले लिए हैं, जिसमें माओवादियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जांच के लिए समितियों का गठन शामिल है। वोटों की खातिर आतंक और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके महागठबंधन के मित्रों के कारण ही आतंक के खिलाफ लड़ाई कमजोर हुई है।

जम्मू और कश्मीर आंतकवादी हमलों का सबसे प्रमुख शिकार हुआ। जम्मू-कश्मीर के लोग इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। पाकिस्तान कभी भी जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने इसके लिए युद्ध तक छेड़े, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। उसने सीमा पार विद्रोह को प्रोत्साहित करने और घरेलू आतंकवादियों का समर्थन करने का सहारा लिया। इस समस्या से निपटने के लिए यूपीए के दस वर्षों के दौरान कांग्रेस के पास कोई ठोस योजना नहीं थी।

कश्मीर और आतंक

जम्मू और कश्मीर आंतकवादी हमलों का सबसे प्रमुख शिकार हुआ। जम्मू-कश्मीर के लोग इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। पाकिस्तान कभी भी जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने इसके लिए युद्ध तक छेड़े, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। उसने सीमा पार विद्रोह को प्रोत्साहित करने और घरेलू आतंकवादियों का समर्थन करने का सहारा लिया। इस समस्या से निपटने के लिए यूपीए के दस वर्षों के दौरान कांग्रेस के पास कोई ठोस योजना नहीं थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरासत में यह मुद्दे मिला। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते को सुधारने के लिए अपने प्रसास जारी किए। उन्होंने पारंपरिक तरीके का प्रयोग इस उम्मीद के साथ किया कि इससे दोनों देशों के बीच एक समझदारी कायम हो, लेकिन पाकिस्तान ने पठानकोट, उरी और पुलवामा के साथ जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने घाटी में मौजूद मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली से बातचीत और जमात-ए-इस्लामी का दबाव अलगाववादियों की विरोध वाली नीति के विरुद्ध था।

पुलवामा और बालाकोट

पुलवामा की आतंकी वारदात में भारत के 41 सीआरपीएफ के जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस घटना ने पूरे देश

की अंतरात्मा को हिला कर रख दिया। हमारे सुरक्षा बलों ने पुलवामा हमले में शामिल कुछ प्रमुख आतंकवादियों को इस घटना के कुछ समय बाद ही समाप्त कर दिया। उरी हमले के बाद हमारी सेना और सरकार के पास नियंत्रण रेखा के पास बने आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों के संबंध में खुफिया जानकारी मिली। सेना ने सितंबर, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया। भारतीय तरफ कोई हताहत नहीं हुआ और उन शिविरों को नष्ट कर दिया गया। हमने 1971 के युद्ध के बाद पहली बार एलओसी को पार किया था।

हमारे सुरक्षा बलों और सरकार को फिर से खुफिया एजेंसियों के माध्यम से बालाकोट में जैश के एक विशाल आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर के संबंध में जानकारी मिली। 26 फरवरी, 2019 को वायु सेना ने हवाई हमले किए और इन शिविरों को नष्ट कर दिया, जिसमें भारी मात्रा में जान-माल की हानि के साथ आतंकवादी ढांचे को गंभीर क्षति हुई।

इन दो हमलों से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत को विकसित किया। क्या हम केवल खुफिया जानकारी के आधार पर हमलों को रोकने और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को अलग-थलग करके ही आतंकवाद से लड़ते रहेंगे? ऐसे मामलों में क्या हम सौ प्रतिशत सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। हमारे खिलाफ बाधाओं को उत्पन्न किया गया है। भले ही आतंकवादी साल में एक बार ही सफल हों, लेकिन वे अपने मनसूबों में कामयाब होते हैं। हमें सुरक्षा के मामले में सौ प्रतिशत सफल होना होगा। यह एक बड़ी चुनौती है। वैकल्पिक रूप से सर्जिकल और एयर स्ट्राइक ने एक नीति विकसित की है कि आतंक के उद्गम पर चोट पहुंचानी होगी। दोनों ही मामलों में हम सफल रहे। पाकिस्तान ने महसूस किया कि अगर उसने आतंक को संरक्षण देना जारी रखा तो इसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी। दुनिया ने हमारे इस सक्रिय दृष्टिकोण का स्वागत किया। पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से अलग-थलग हुआ है। उसके पारंपरिक मित्र उसका साथ छोड़ रहे है।

राजनीतिक लड़ाई

केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लगातार मजबूत से लड़ाई लड़ी। जेएनयू से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस ने उनका साथ दिया है। घाटी में कश्मीरी जेहादियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने वाले वामपंथी उग्रवादियों की संख्या बढ़ी है। कांग्रेस आतंक के स्रोत पर ही नष्ट करने वाले सक्रिय दृष्टिकोण के विचार का विरोध नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर इस सक्रिय दृष्टिकोण के राजनीतिक प्रभाव से वह परेशान है। पुलवामा की निंदा करने पर कांग्रेस सरकार के साथ एक है, लेकिन बालाकोट को लेकर परेशान है। इस प्रकार वह सर्जिकल स्ट्राइक को निरंतर एक विवादित मुद्दा बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस यह तर्क देता है कि ऐसे हमले अतीत में हो चुके हैं। वह इसका श्रेह प्रधानमंत्री मोदी को नहीं देना चाहती। हवाई हमलों पर, उनका आचरण और भी संदिग्ध है। पहले दो दिनों भारतीय वायु सेना के साथ सहानुभूति रखते हुए, उन्होंने इस मुद्दे पर चौतरफा हमले शुरु कर दिए। कांग्रेस ने हमलें की सफलता पर सवाल उठाए। उन्होंने सबूत मांगना शुरू कर दिया कि बालाकोट में कितने आतंकवादी मारे गए। उन्होंने यहां तक कहा कि यह हमला आतंक के खिलाफ नहीं, बल्कि आगामी चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। घरेलू राजनीति साधने के लिए यह कांग्रेस द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा था। लेकिन ऐसा करके कांग्रेस पाकिस्तान के हाथों में खेल रही थी, जहां राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं के बयान पाकिस्तान में टेलीविजन चैनलों पर दिखाए गए। पाकिस्तान सरकार ने अपनी झूठी बातों को सही साबित करने के लिए इन बयानों का हवाला दिया।

2019 के आम चुनावों में मतदाताओं के सामने विकल्प है। क्या नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद के एक अति-सहयोगी दल को सत्ता में रखा जा सकता है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने वालों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या इन चुनावों में पाकिस्तान के हाथों में खेलने वालों को कड़ा सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर एक बड़ा 'हां' है। यह देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सुरक्षित महसूस करता है।

अब अंतिम प्रश्न यह उठाता है। जब भारत अल्ट्रा-लेफ्ट और जेहादी आतंकवादियों से लड़ता है, तब उसे सीमा पार आतंकवाद के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है, तो भारत को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? 2019 के आम चुनावों में मतदाताओं के सामने विकल्प है। क्या नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद के एक अति-सहयोगी दल को सत्ता में रखा जा सकता है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने वालों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या इन चुनावों में पाकिस्तान के हाथों में खेलने वालों को कड़ा सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर एक बड़ा 'हां' है। यह देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सुरक्षित महसूस करता है। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त मंत्री हैं)

मनोहर पर्रिकर: सादगी को आत्मसात करने वाले मुख्यमंत्री

मनोहर पर्रिकर सक्रिय लेकिन स्वच्छ राजनीति में विश्वास करते थे। वह उन निस्वार्थ राजनेताओं में से एक थे जिन्हें मैंने जाना है। वह हमेशा पार्टी के निर्देशों का पालन करने वाले राजनेता थे। उन्होंने सही मायने में हमारी पार्टी की राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट की भावना को प्रासंगिक बनाया।

नितिन गडकरी

मेरे मित्र मनोहर पर्रिकर के साथ मेरी आखिरी मुलाकात 27 जनवरी को हुई थी। उन्होंने गोवा में मंडोवी नदी पर तीसरे पुल के उद्घाटन के लिए अपने आवास पर अस्थायी चिकित्सालय से उद्घाटन स्थल पर आकर सभी को चौंका दिया। मनोहर पर्रिकर ने मुझे बताया कि वह इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनना चहाते है और गोवा को शीघ्र और सर्वांगीण विकास में मदद करने के लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया।

जैसा कि मैं उसके बगल में बैठा था और मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। उनकी आवाज़ बेहद कमज़ोर थी और उनकी नाक में फीडर ट्यूब डाली गई थी। फिर भी, वह बेचैन नहीं दिख रहे थे। जो दिखाई दे रहा था, वह गोवा के लोगों की आखिरी सांस तक सेवा करने के लिए अदम्य "जोश" था, जैसाकि उनका सारा जीवन रहा। तीन दिन बाद, 30 जनवरी को मनोहर ने गोवा विधानसभा में उसी हालत में बजट को भी पेश किया और सदन को लगभग दो घंटे तक संबोधित किया गया। 4 फरवरी को उन्होंने दुनिया को एक बहादुर संदेश ट्वीट किया: "मनुष्य का मन किसी भी बीमारी को दूर कर सकता है।"

जैसाकि मैंने मनोहर पर्रिकर के साथ बिताए अपने सभी क्षणों के बारे में सोचा, तो मैं केवल यह कह सकता हूं कि उनकी अखंडता, समर्पण और कड़ी मेहनत के अलावा, वह कैंसर रोगियों के लिए एक भी एक प्रेरणा बन गए हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि कोई भी बीमारी देश के लिए आपकी प्रतिबद्धता को खत्म नहीं कर सकती है।

सार्वजनिक जीवन में मनोहर मेरे समकालीन थे। उसके साथ मेरा जुड़ाव लगभग 35 साल पुराना है। हम दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, उसके अनुशासन और राष्ट्र-निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की भावना से प्रेरित थे।

वह एक शानदार छात्र थे, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से बीटेक किया। उन्होंने राज्य में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदेश पर गोवा की राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने 1994 में पणजी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर राज्य की विधानसभा में प्रवेश किया और न केवल राज्य की राजनीति, बल्कि केंद्र में भी देश के रक्षा मंत्री के रूप में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी।

रक्षा मंत्री के रूप में पर्रिकर का कार्यकाल कई मायनों में ऐतिहासिक था। वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की गई, राफेल सौदे को अंतिम रूप दिया गया और भारत ने उरी हमले के जवाब में पीओके में सफल सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। हालांकि, अपने निजी जीवन में मनोहर सादगी और मितव्ययी

वह एक शानदार छात्र थे, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से बीटेक किया। उन्होंने राज्य में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदेश पर गोवा की राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने 1994 में पणजी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर राज्य की विधानसभा में प्रवेश किया और न केवल राज्य की राजनीति, बल्कि केंद्र में भी देश के रक्षा मंत्री के रूप में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी।

जीवन का प्रतीक बने रहे। कुछ साल पहले तक, वह कभी-कभी सीएम बनने के बाद भी ऑफिस जाने के लिए स्कूटर चलाते थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अक्सर कम लागत वाली एयरलाइनों की इकोनॉमी वर्ग में यात्रा की। उसकी जरूरतें कम से कम थीं, लेकिन उनके ख्याल काफी व्यापक थे।

मनोहर पर्रिकर सक्रिय लेकिन स्वच्छ राजनीति में विश्वास करते थे। वह उन निस्वार्थ राजनेताओं में से एक थे जिन्हें मैंने जाना है, वह हमेशा पार्टी के निर्देशों का पालन करने वाले राजनेता थे। उन्होंने सही मायने में हमारी पार्टी की राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट की भावना को प्रासंगिक बनाया। अक्टूबर 2000 में मनोहर ने गोवा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ बिना खरीद-फरोख्त किये आंतरिक तख्तापलट किया।

मनोहर पर्रिकर सक्रिय लेकिन स्वच्छ राजनीति में विश्वास करते थे। वह उन निस्वार्थ राजनेताओं में से एक थे जिन्हें मैंने जाना है, वह हमेशा पार्टी के निर्देशों का पालन करने वाले राजनेता थे। उन्होंने सही मायने में हमारी पार्टी की राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट की भावना को प्रासंगिक बनाया। अक्टूबर 2000 में मनोहर ने गोवा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ बिना खरीद-फरोख्त किये आंतरिक तख्तापलट किया।

वह चार बार गोवा के सीएम रहे, पर्रिकर ने बुनियादी ढांचें से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाने और भ्रष्टाचार को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तो मैं अपने सुशासन के एजेंडे को विकसित करने के लिए और नए विचारों एवं पहलों के लिए लगातार उनकी ओर देखता रहा।

मनोहर रक्षा मंत्री का पद छोड़कर मार्च 2017 में सीएम के रूप में गोवा लौट आए, गोवा फारवर्ड पार्टी और एमजीपी जैसे दलों ने मनोहर के नेतृत्व वाली सरकार को अपना समर्थन दिया। चूंकि गोवा चुनावों का प्रभारी था, इसलिए मेरे पास कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने और एक साथ काम करने की दिलचस्प यादें हैं।

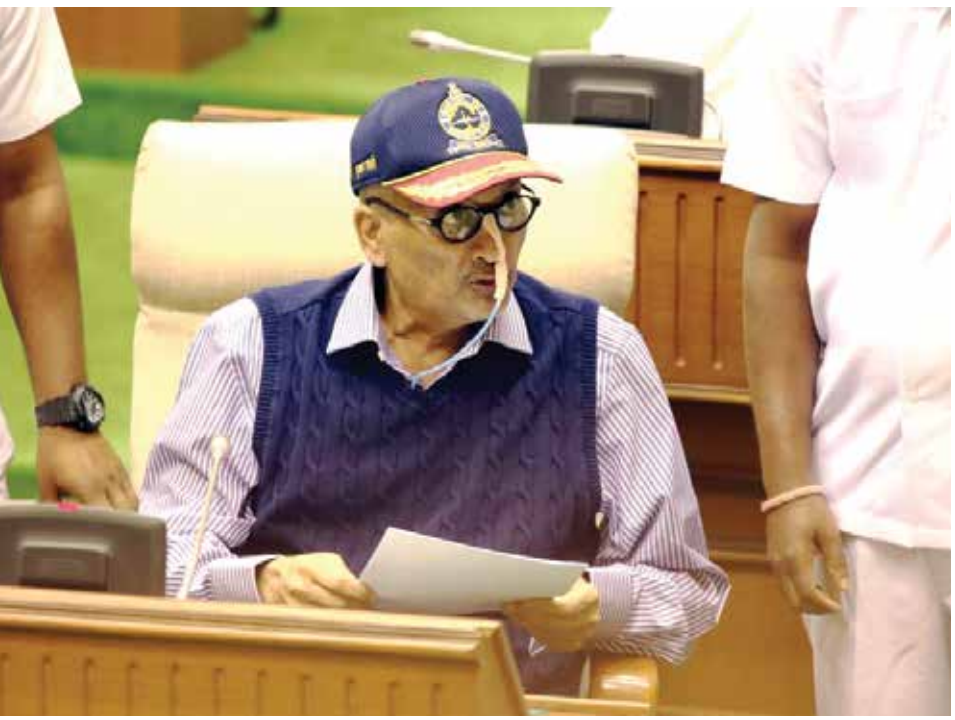

हालांकि, फरवरी 2018 से मनोहर कैंसर से जूझ रहे थे। अग्नाशय के कैंसर में जीवन की उम्मीद कम ही होती है। लेकिन इस लड़ाई के माध्यम से मनोहर के उत्साह और ऊर्जा को देखते हुए हमें उम्मीद थी कि वह अपने जीवन का सबसे बड़ा तख्तापलट कर देगा।

लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जैसा कि मैंने मनोहर के साथ अपने जुड़ाव को याद किया, मुझे एक और महत्वपूर्ण बात बतानी है - मेरी जानकारी में कभी भी गोवा जैसे किसी छोटे राज्य के नेता पूरे भारत में स्वीकृति और लोकप्रियता नहीं मिली। कारण सरल हैः मनोहर पर्रिकर सादगी को आत्मसात करने वाले मुख्यमंत्री, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि आप जिस तरह के रिश्ता उनके साथ बनाना चाहे वह बड़ी सरलता से उसे अपनाते थे, फिर चाहे आप उनसे किसी सरकारी कार्यालय या सब्जी मंडी में ही क्यों न मिले हों।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर को आधुनिक गोवा का निर्माता बताया है। मनोहर की मृत्यु प्रत्येक गोवा वासी और प्रत्येक भारतीय के लिए एक क्षति है। मेरे लिए यह नुकसान अत्यंत व्यक्तिगत है। ■

(लेखक केन्द्रिय मंत्री हैं)

भरोसे और विकास के दो बरस: यूपी की भाजपा सरकार ने तमाम क्षेत्रों में वह कर दिखाया जो एक मिसाल है

योगी आदित्यनाथ

फरवरी 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जिस संकल्प पत्र को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच गई थी। वह संकल्प पत्र हमारी सोच ही नहीं अपितु प्रदेश के विकास की आत्मा भी है। मुझे प्रसन्नता होती है कि हमारी पार्टी ने चुनाव के दौरान जितने भी वायदे किए थे, सिर्फ 24 महीने में उनमें से अधिकांश पूरे हो चुके हैं।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार

किसानों की कर्ज माफी, पिछला गन्ना मूल्य भुगतान, न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे किसानों के खाते में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, गुंडाराज और भ्रष्टाचार की समाप्ति, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, हर गरीब को आवास, स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को शौचालय, प्रमुख सांस्कृतिक नगरों को पर्यटन के मुख्य केंद्र के तौर पर विकसित करने जैसे कई संकल्प हमारी सरकार पूरे कर चुकी है।

किसानों की कर्ज माफी, पिछला गन्ना मूल्य भुगतान, न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे किसानों के खाते में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, गुंडाराज और भ्रष्टाचार की समाप्ति, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, हर गरीब को आवास, स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को शौचालय, प्रमुख सांस्कृतिक नगरों को पर्यटन के मुख्य केंद्र के तौर पर विकसित करने जैसे कई संकल्प हमारी सरकार पूरे कर चुकी है।

सत्ता में आने के पहले

19 मार्च 2017 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के पहले तक प्रदेश में अराजकता, असुरक्षा एवं किस्म-किस्म के घोटालों और नियुक्तियों में धांधली का बोलबाला था। ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर रिश्वतखोरी एक उद्योग बन चुका था। शिक्षा माफिया हावी थे। माफिया को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। सत्ता संरक्षण पाए अपराधियों के कारण कैराना और कांधला जैसे कस्बों से सैकड़ों परिवार पलायन कर रहे थे।

जीरो टॉलरेंस की नीति

हमारी सरकार द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई और पुलिस की कार्यप्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त किया गया। परिणाम यह है कि बीते दो बरस में प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ। अपहरण और एसिड अटैक की कोई घटना नहीं हुई। पुलिस और अपराधियों के बीच हुई 3454 मुठभेड़ों में 7975 अपराधी गिरफ्तार हुए, 1002 अपराधी घायल हुए और 73 मारे गए। 11,981 अपराधियों ने जमानत निरस्त कराकर आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच दुखद यह रहा कि इस मुहिम में हमारी पुलिस के पांच बहादुर जवान भी शहीद हुए। अब राज्य में कानून का राज कायम है। संगठित अपराधों पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। 18000 से अधिक भूमाफिया एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के द्वारा अवैध रूप से अर्जित लगभग हजारों करोड़ रुपये मूल्य की संपति जब्त की गई है। महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाने हेतु हर जिले में पहली बार एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया।

कुशल वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2016-17 में राज्य का राजकोषीय घाटा, जीडीपी का 4.5 प्रतिशत था। हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से वर्ष 2017-18 में यह घाटा जीडीपी का 2.97 प्रतिशत हो गया। पूर्ववर्ती सरकार का राजस्व अधिशेष 1.6 प्रतिशत था, जबकि हमारी सरकार में यह अधिशेष बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया है। 341 किमी. लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने के लिए 600 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 380 किमी लंबे झांसी-चित्रकूट-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन बनाने के कार्य की स्वीकृति के साथ साथ राज्य में 1,16,392 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है।

3700 किमी लंबे मार्ग का नवीनीकरण हो या फिर ग्रामीण इलाके में 4577 किमी सड़क निर्माण, सरकार ने दो साल में यह करके दिखाया। वायु परिवहन को भी बेहतर किया है।

आयुष्मान भारत

प्रदेश में आयुष्मान भारत के तहत 6 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की निशुल्क चिकित्सा बीमा सुविधा दी जा रही है। गैर बीपीएल आबादी के 55 लाख लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है। 2329 उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेड किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश के 10 जिलों में 50 बेड के एकीकृत अस्पताल खोलने का काम शुरू हुआ है। महिला सशक्तीकरण के तहत उज्ज्वला योजना में महिलाओं को 1 करोड़ 12 लाख निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए है। सरकार 24 महीने में पीएम आवास योजना (शहरी) में 11 लाख से अधिक आवास स्वीकृत कर चुकी है। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में भी 12 लाख 82 हजार आवास गरीबों के लिए मंजूर किए गए हैं। 24 महीने में 2.49 करोड़ शौचालय बनाकर बेस लाइन सर्वे के अनुसार उप्र को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है।

जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली

पिछली सरकार द्वारा मात्र पांच वीआईपी जनपदों को बिजली दी जा रही थी। पिछले 24 महीनों में प्रदेश के 2 लाख 84 हजार मजरे रौशन किए जा चुके हैं। 'सौभाग्य योजना' के तहत 75 लाख से अधिक गरीब परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। हमारी सरकार जनपद मुख्यालय पर बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत उपलब्ध करा रही है। हमारी सरकार द्वारा 36 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से लाखों लघु एवं सीमांत किसानों की एक लाख रुपये तक की कर्ज माफी की गई है। वर्ष 2018-19 में खरीफ फसल हेतु 31 लाख किसानों का फसल बीमा किया गया, जिनमें लगभग पांच लाख प्रभावित किसानों को 364 करोड़ रुपये तक क्षतिपूर्ति की गई। वर्षों से लंबित बाणसागर परियोजना को हमने पूरा कराया। इससे कृषि सिंचित क्षेत्र 1.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा और 1.70 लाख किसान लाभान्वित हुए।

गेहूं की सरकारी खरीद

वर्ष 2016-17 में 7.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई थी, जबकि वर्ष 2017-18 में 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद किसानों से सीधे गई। वर्ष 2018-19 में 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई और किसानों के खातों में 9231.99 करोड़ रुपये का ऑनलाइन भुगतान 72 घंटे के अंदर किया गया। ऐसा ही धान खरीद में भी किया गया है। सरकार रबी विपणन वर्ष 2019-20 हेतु मूल्य समर्थन योजना के तहत 55 लाख मी. टन गेहूं खरीदेगी। सरकार ने 2011-12 से लेकर 2017-18 तक के गन्ना मूल्य बकाया 57 हजार 578 करोड़ रुपये का भुगतान डेढ़ साल में कर दिखाया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के एक करोड़ 3 लाख किसानों को पहली किस्त दी जा चुकी है।

बीते दो साल में स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 18490 रोजगार का सृजन किया गया। 633 रोजगार मेले आयोजित कर 1,21,194 से अधिक युवाओं को सेवा से जोड़ा है। सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाते हुए प्रदेश के 2 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरियां दी हैं।

रोजगार का सृजन

बीते दो साल में स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 18490 रोजगार का सृजन किया गया। 633 रोजगार मेले आयोजित कर 1,21,194 से अधिक युवाओं को सेवा से जोड़ा है। सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाते हुए प्रदेश के 2 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरियां दी हैं। दो वर्ष में उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश हुआ है। इससे कम से कम 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। आज प्रदेश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सरकार ने 2018 में उप्र इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन कराया जिसमें 1045 एमओयू हस्ताक्षरित हुए। 4.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश हो चुका है। सरकार ने पारंपरिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के कौशल को निखार कर उनके रोजगार हेतु विश्वकर्मा श्रम योजना प्रारंभ की है। 6 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं मानदेय देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कुंभ दर्शन

हाल में विश्व के महानतम सांस्कृतिक समागम कुंभ में देश-दुनिया के 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं-पर्यटकों ने कुंभ दर्शन किया। यह आयोजन स्वच्छता एवं सुरक्षा के सभी मानकों पर खरा उतरा। कुल मिलाकर अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश पर हर कोई गौरव की अनुभूति कर सकता है। ■

(लेखक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

(दैनिक जागरण से साभार)

विजय संकल्प रैली, आगरा (उत्तर प्रदेश)

देश को नरेन्द्र मोदी जैसा ही पीएम चाहिए जो सबका विकास करे: अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 24 मार्च 2019 को आगरा में विजय संकल्प रैली में विपक्ष पर कड़े प्रहार किए। श्री शाह ने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता सिर्फ इसलिए वोट नहीं दे सकती कि किसी की प्रधानमंत्री बनने की हसरत में उम्र निकली जा रही है या किसी को पीएम बनने का शौक चढ़ा है। भाजपा अध्यक्ष ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि एक ओर देश का विकास करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी सरकार पर 5 साल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप तक नहीं लगा तो दूसरी तरफ महागठबंधन और महामिलावट है, जो जाति-धर्म वाली सरकार चाहते हैं।

सभा को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा, 'हमें देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री को चुनना है, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चुनना है जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सके ना कि सिर्फ इसलिए कि किसी की उम्र निकली जा रही है या किसी को पीएम बनने का शौक चढ़ा है। एक ओर मोदीजी हैं तो दूसरी ओर महागठबंधन और महामिलावट है। इनसे कोई पूछे कि अगर आप जीते तो पीएम कौन बनेगा। इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा।'

श्री शाह ने कहा, 'मायावती जी कहती हैं कि मोदीजी को हटाया जाए, मगर पूछो चुनाव कहां से लड़ेंगी तो कहेंगी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू सब कह रहे हैं कि मोदीजी को हटाना है, मगर पूछो आप चुनाव कहां से लड़ोगे तो ये सब कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीते 70 सालों में कांग्रेस और उनके चट्टे-बट्टों ने शासन किया, लोगों को अहसास ही नहीं था कि देश आजाद भी है।'

उन्होंने कहा, 'बिना किसी की जाति-धर्म पूछे 6 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। मोदीजी ने बिना किसी की जात-पात पूछे 13 करोड़ किसानों के खाते में 6 हजार रुपये देने का फैसला किया।' उन्होंने लोगों से पूछा कि आप जाति-धर्म करने वाली सरकार चाहते हैं या देश का विकास करने वाली सरकार चाहिए। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार और 2 साल की योगी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा।

श्री शाह ने कहा, 'यूपीए सरकार के दौरान पाकिस्तान हमारे सैनिकों को ले जाता था और सिर काटकर भेजता था, लेकिन 'मौनी बाबा' वाली सरकार के माथे पर जूं नहीं रेंगी। मोदीजी की सरकार के दौरान उन्होंने उरी पर हमला किया, उन्हें लगा कि फिर 'मौनी बाबा' जैसी सरकार होगी। मगर मोदीजी ने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है।'

श्री शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेना से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। उनके इन सवालों पर पाकिस्तान की संसद में तालियां बजती हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव गरीबों के विकास, देश की सुरक्षा और विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने जैसे मुद्दों पर लड़ना चाहिए ना कि किसी का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए।

इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का माध्यम जाति, धर्म, क्षेत्र या संप्रदाय नहीं बल्कि गांव, देहात, गरीब महिला सभी को बनाया है। ढाई करोड़ से ज्यादा परिवारों को शौचालय, 1 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। अगर आपको हमारी सफलता का पैमाना देखना है तो प्रयागराज में हुए भव्य कुंभ को देख लीजिए। यह नमामि गंगे की सफलता ही थी कि गंगा अविरल भी थी, निर्मल भी थी। आजादी के बाद से क्यों कभी किसी प्रधानमंत्री ने अक्षयवट को खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई? वे लोग डरते थे, मगर मोदीजी ने यह काम करके दिखाया।' ■

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई

आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए केन्द्र सरकार ने 22 मार्च को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के तहत जेकेएलएफ (यासीन गुट) को गैर कानूनी संगठन करार दिया।

- केन्द्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति का पालन किया है और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सुरक्षाबलों को आतंक से लड़ने के लिए खुली छूट दी गई है।
- सरकार अलगाववादी संगठनों के गतिविधियों पर रोक लगाने की नीति का पालन कर रही है। ऐसी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। एनआईए और प्रर्वतन निदेशालय इन संगठनों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है।
- उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 28 फरवरी 2019 को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के प्रावधानों के तहत जमात-ए-इस्लामी (जेएंडके) को गैर कानूनी संगठन करार दिया है।
- उस समय यह स्पष्ट किया गया था कि जमात-ए-इस्लामी (जेएंडके), जमात ए इस्लामी हिंद से अलग है। 1953 में इसने अपना संविधान बनाया। जमात-ए-इस्लामी (जेएंडके) हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के गठन के लिए जिम्मेदार है। हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) जम्मू कश्मीर में सक्रिय सबसे बड़ा आतंकी गुट है। जमात-ए-इस्लामी (जेएंडके) हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) को भर्ती, धन, स्थान, लॉजिस्टिक आदि सभी तरह की सहायता उपलब्ध कराता है।
- मो. यासीन मलिक के नेतृत्व में जम्मू व कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट ने घाटी में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। 1988 से यह अलगाववादी गतिविधियों की अगुवाई करता रहा है और हिंसा फैलाता रहा है। 1989 में जेकेएलएफ द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी। इस घटना का मास्टर माइंड मो. यासीन मलिक था। इसके बाद कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन कर गये। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए और उनकी हत्या के लिए मो. यासीन मलिक दोषी है।
- जेकेएलएफ के खिलाफ कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। यह संगठन भारतीय वायु सेना के चार सैन्य कर्मियों की हत्या तथा डॉक्टर रूबैया सईद (बीपी सिंह सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी) के अपहरण का जिम्मेदार है। यह संगठन आतंकवाद को फैलाने के लिए अवैध धन के इस्तेमाल के लिए भी जिम्मेदार है। जेकेएलएफ ने धन इक्ट्ठा करने और इसे पत्थर फेंकने वालों को वितरित करने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है।
- जेकेएलएफ (वाई) की गतिविधियां देश की सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और सम्प्रभुता के लिए गंभीर खतरा हैं। यह संगठन वैधानिक रूप से बनी सरकार के खिलाफ शत्रुता की भावना व घृणा फैलाने तथा सशस्त्र विद्रोह पैदा करने के लिए सक्रिय है।
- जेकेएलएफ के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने 37 एफआईआर दर्ज किये हैं। सीबीआई ने भी दो मामले दर्ज किये हैं। इनमें भारतीय वायु सेना के सैन्य कर्मियों की हत्या का मामला भी शामिल है। एनआईए ने भी एक मामला दर्ज किया है जिसकी जांच चल रही है। स्पष्ट है कि जेकेएलएफ अलगाववाद तथा आतंकवाद को समर्थन देने तथा उकसाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है।

- सरकार बड़ी संख्या में अलगाववादी नेताओं को सुरक्षा प्रदान करती है। समीक्षा के बाद सरकार ने ऐसे कई नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
- सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 2005 के बाद पहली बार 2018 में शहरी स्थानीय निकायों तथा 2011 के बाद पंचायतों का शांतिपूर्ण चुनाव संचालित किया। इन चुनावों में लोगों ने सक्रिय भागीदारी की और औसत मतदान 74 प्रतिशत रहा। इन चुनावों में 3652 सरपंच और 23629 पंच चुने गये। पंचायतों को सशक्त बनाया गया है और उन्हें आम लोगों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया गया है। सरपंचों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित किये गये। पंचायतों की वित्तीय क्षमता को 10 गुना बढ़ाया गया। लगभग 20 विभागों को पंचायती राज के अंतर्गत लाया गया है। सरकार जम्मू, कश्मीर और लद्दाख– तीनों क्षेत्रों के सम्मिलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ■

लोकतंत्र के लिए चार अनुरोध

लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के मतदान में अब महीने भर से भी कम समय है। मतदान हमारे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। हमारा वोट देश की विकास यात्रा में हमारी भागीदारी का संकल्प है। मताधिकार का प्रयोग कर हम देश के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं।

आइए, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जहां वोटर कार्ड पाना और वोट देना गर्व की बात हो, सब लोग इसको लेकर उत्साहित हों। विशेषकर पहली बार वोट डालने वालों के लिए तो यह लोकतंत्र का उत्सव ही बन जाए। माहौल ऐसा बने कि वोट नहीं कर पाने पर व्यक्ति को पश्चाताप हो। फिर कभी देश में कुछ भी गलत दिखे तो व्यक्ति अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार माने और सोचे कि यदि मैं उस दिन वोट करने गया होता तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं होती और देश मुसीबत नहीं झेलता। हमें अपने जीवन में ऐसा पछतावा न करना पड़े, इसके लिए वोट अवश्य दें। आज मैं आप लोगों से चार अनुरोध करना चाहता हूं:

(1) आज ही रजिस्टर करें

- वोटर कार्ड होना हर एक के लिए गर्व का विषय हो।
- अगर आपने अपने आपको वोटर के रूप में रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें।
- आप www.nvsp.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पोलिंग स्टेशन के BLOs यानी बूथ लेवल ऑफिसर से या फिर मतदाता पंजीकरण कार्यालय में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
- 2019 का चुनाव बहुत ही खास है, क्योंकि 21वीं सदी में जन्म लेने वाले युवाओं को वोट करने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जिन युवाओं को वोट देने का अधिकार है और अब तक खुद को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द ऐसा करेंगे और हमारे महान लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे।

(2) अपने नाम की जांच मतदाता सूची में अच्छे से कर लें

- समय रहते एक बार फिर से मतदाता सूची को देखें और ये जांच लें कि उसमें आपका नाम दर्ज है या नहीं।
- आप अपने राज्य के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर भी मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं।
- अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो संबंधित कर्मचारी को इसके बारे में बताएं। अगर आपने अपना घर बदला है तो ये सुनिश्चित करें कि जहां आप रहने गए हैं, वहां की मतदाता सूची में आपका नाम हो।
- आपके क्षेत्र में जिस चरण में मतदान होना है, उसके लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक मतदाता सूची में सुधार का काम जारी रहता है, लेकिन अंतिम तारीख तक इंतजार नहीं करें और आज ही अपना नाम जुड़वा लें।

(3) अपने कार्यक्रम सोच समझ कर तय करें

- चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आने वाले दिनों की योजना इस तरह बनाएं कि आप मतदान के दिन उपलब्ध हों। अगर आपने गर्मी की छुट्टी में बाहर जाने की योजना बनाई है तो मतदान से पहले या फिर बाद में जाएं।
- अगर आपके वोट डालने की जगह और आपके काम करने की जगह अलग-अलग है तो वोट डालने के लिए आप जा पाएं, यह अभी से सुनिश्चित करें। आपका एक वोट राष्ट्र का भविष्य तय करेगा, इसलिए जरूरत पड़े तो वोट डालने के लिए छुट्टी भी लें।

(4) दूसरों को भी प्रेरित करें

- आप अपने परिवार के सदस्यों और साथियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।
- जरूरत पड़े तो मतदान के दिन वोट देने के लिए उन्हें साथ लेकर जाएं।
- अधिक से अधिक मतदान का मतलब है, एक मजबूत लोकतंत्र और एक मजबूत लोकतंत्र से ही विकसित भारत बनेगा।
- हमने देश में पिछले कुछ चुनावों में रिकॉर्ड मतदान देखा है।
- लोकतंत्र की इस महान परंपरा को और मजबूती देने के लिए मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें।
- मैं अलग-अलग क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों, राजनीति, उद्योग, खेल और फिल्म जगत के लोगों से कहना चाहूंगा कि वे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आगे आएं। हम सब लोग मिलकर यह दिखा दें कि इस बार अभूतपूर्व मतदान होगा और इस बार का मतदान देश के चुनावी इतिहास के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ■

विपक्ष आतंकवाद के समर्थकों की शरणस्थली है: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा आतंकवादी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में भारतीय वायु सेना के हवाई हमले को लेकर विपक्षी दलों पर 22 मार्च को प्रहार करते हुए विपक्ष को ''आतंकवाद के समर्थकों की शरणस्थली" बताया और उस पर सशस्त्र सेनाओं का ''अपमान" करने का आरोप लगाया। साथ ही, भाजपा के अन्य नेताओं ने भी पुलवामा आतंकवादी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में भारतीय वायु सेना के हवाई हमले को लेकर विपक्ष के रूख की आलोचना की।

'जनता माफ नहीं करेगी' हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए श्री मोदी ने ट्वीट में कांग्रेस के विदेश मामलों को देखने वाले सैम पित्रोदा की यह कहने के लिए आलोचना की कि मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत हवाई हमले से जवाब दे सकता था, लेकिन ''मेरे हिसाब से दुनिया से ऐसे नहीं निपटा जाता।"

श्री मोदी ने कहा, ''कांग्रेस के शाही वंश के वफादार दरबारी ने माना था जो दुनिया पहले से ही जानती है कि कांग्रेस आतंकवाद की ताकतों को जवाब नहीं देना चाहती थी। यह नया भारत है- हम आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे।"

उन्होंने कहा, ''विपक्ष ने बार-बार हमारी सेनाओं का अपमान किया है। मैं अपने साथी भारतीयों से अपील करता हूं कि विपक्षी नेताओं पर उनके बयानों को लेकर सवाल उठाएं। उन्हें बताएं कि 130 करोड़ भारतीय विपक्ष को उनकी हरकतों के लिए माफ नहीं करेंगे या भूलेंगे नहीं। भारत हमारी सेनाओं के साथ दृढ़ता से खड़ा है।"

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने विपक्ष के रवैये पर ट्विटर पर लिखा कि ''उनका दिल आतंकवादियों के लिए धड़कता है जबकि हमारा दिल तिरंगे के लिए धड़कता है।" श्री शाह ने ट्वीट किया, ''विपक्ष और भाजपा के बीच अंतर साफ है। वे हमारी सेना पर संदेह करते हैं, हमें अपनी सेना पर गर्व है। उनका दिल आतंकवादियों के लिए धड़कता है, हमारा दिल तिरंगे के लिए धड़कता है।" उन्होंने कहा, ''इस चुनाव में अपनी वोट की ताकत के जरिए कांग्रेस की संस्कृति पर सर्जिकल स्ट्राइक करें।"

विपक्ष और भाजपा के बीच अंतर साफ है। वे हमारी सेना पर संदेह करते हैं, हमें अपनी सेना पर गर्व है। उनका दिल आतंकवादियों के लिए धड़कता है, हमारा दिल तिरंगे के लिए धड़कता है।

केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली ने पित्रोदा की टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तानी समाचार चैनलों पर हिट होंगे। वित्त मंत्री ने कहा, ''वह मानते हैं कि हमने जो किया (बालाकोट हवाई हमला) वह गलत था। किसी भी दूसरे देश ने नहीं कहा कि यह गलत था। यहां तक कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी ऐसी बात नहीं कही। यह केवल पाकिस्तान की राय है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग किसी राजनीतिक पार्टी के लिए रोल मॉडल होते है।"

इससे पहले एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव की आलोचना की। यादव ने आरोप लगाया कि वोट हासिल करने के लिए पुलवामा हमला एक ''षडयंत्र" था।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''विपक्ष आतंकवाद के समर्थकों और हमारी सशस्त्र सेनाओं पर सवाल उठाने वालों की शरणस्थली रहा है। राम गोपाल जी जैसे किसी वरिष्ठ नेता का यह निंदनीय बयान उन सभी का अपमान करता है जिन्होंने कश्मीर की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। यह हमारे शहीदों के परिवारों का अपमान करता है।" ■

संस्थाओं का सम्मान और संस्थाओं की अवमाननाः दो परस्पर विरोधी अप्रोच

नरेन्द्र मोदी

वह 2014 की गर्मियों के दिन थे, जब देशवासियों ने निर्णायक रूप से मत देकर अपना फैसला सुनायाः

परिवारतंत्र को नहीं, लोकतंत्र को चुना।

विनाश को नहीं, विकास को चुना।

शिथिलता को नहीं, सुरक्षा को चुना।

अवरोध को नहीं, अवसर को प्राथमिकता दी।

वोट बैंक की राजनीति के ऊपर विकास की राजनीति को रखा।

2014 में देशवासी इस बात से बेहद दुखी थे कि हम सबका प्यारा भारत आखिर फ्रेजाइल फाइव देशों में क्यों है? क्यों किसी सकारात्मक खबर की जगह सिर्फ भ्रष्टाचार, चहेतों को गलत फायदा पहुंचाने और भाई-भतीजावाद जैसी खबरें ही हेडलाइन बनती थीं। तब आम चुनाव में देशवासियों ने भ्रष्टाचार में डूबी उस सरकार से मुक्ति पाने और एक बेहतर भविष्य के लिए मतदान किया था।

वर्ष 2014 का जनादेश ऐतिहासिक था। भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर वंशवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। जब कोई सरकार 'Family First' की बजाए 'India First' की भावना के साथ चलती है तो यह उसके काम में भी दिखाई देता है। यह हमारी सरकार की नीतियों और कामकाज का ही असर है कि बीते पांच वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है।

हमारी सरकार के दृढ़संकल्प का ही नतीजा है कि आज भारत ने सेनिटेशन कवरेज में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 2014 में जहां स्वच्छता का दायरा महज 38% था, वो आज बढ़कर 98% हो गया है। हमारी सरकार के प्रयासों से ही हर गरीब का आज बैंक में खाता है। जरूरतमंदों को बिना बैंक गारंटी के लोन मिले हैं। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। बेघरों को घर उपलब्ध कराए गए हैं। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा की सुविधा मिली है और युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले हैं।

आज हर क्षेत्र में हुए इस बुनियादी परिवर्तन का अर्थ यह है कि देश में एक ऐसी सरकार है, जिसके लिए देश की संस्थाएं सर्वोपरि हैं। भारत ने देखा है कि जब भी वंशवादी राजनीति हावी हुई तो उसने देश की संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया।

संसद

16वीं लोकसभा की कुल प्रोडक्टिविटी शानदार तरीके से 85% रही, जो 15वीं लोकसभा से कहीं अधिक है। वहीं 2014 से 2019 के बीच राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 68% रही। अंतरिम बजट सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी जहां 89% रही, वहीं राज्यसभा में यह महज 8% देखी गई। दोनों सदनों की प्रोडक्टिविटी के इन आंकड़ों का क्या अर्थ है, इसे देश भली-भांति जानता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी किसी गैर वंशवादी पार्टी की संख्या सदन में अधिक होती है तो उसमें स्वाभाविक रूप से अधिक काम करने की प्रवृत्ति होती है।

देशवासियों को यह पूछना चाहिए कि आखिर राज्यसभा ने उतना काम क्यों नहीं किया, जितना लोकसभा में हुआ? वे कौन सी शक्तियां थीं, जिन्होंने सदन के भीतर इतना हंगामा किया और क्यों?

प्रेस और अभिव्यक्ति

वंशवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां कभी भी स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के साथ सहज नहीं रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया सबसे पहला संवैधानिक संशोधन फ्री स्पीच पर रोक लगाने के लिए ही था। फ्री प्रेस की पहचान यही है कि वो सत्ता को सच का आईना दिखाए, लेकिन उसे अश्लील और असभ्य की पहचान देने की कोशिश की गई।

यूपीए के शासनकाल में भी ऐसा ही देखने को मिला, जब वे एक ऐसा कानून लेकर आए, जिसके मुताबिक अगर आपने कुछ भी 'अपमानजनक' पोस्ट कर दिया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यूपीए के ताकतवर मंत्रियों के बेटे के खिलाफ एक ट्वीट भी निर्दोष आदमी को जेल में डाल सकता था।

कुछ दिनों पहले ही देश ने उस डर के साये को भी देखा, जब कुछ युवाओं को कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया जहां कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि किसी भी तरह की धमकी से जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली है। अगर वे जबरदस्ती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास करेंगे, तब भी कांग्रेस को लेकर लोगों की धारणा नहीं बदलेगी।

संविधान और न्यायालय

25 जून, 1975 की शाम जब सूरज अस्त हुआ, तो इसके साथ ही भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की भी तिलांजलि दे दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा जल्दबाजी में दिए गए रेडियो संबोधन को सुनें तो स्पष्ट होता है कि कांग्रेस एक वंश की रक्षा करने के लिए किस हद तक

जा सकती है। आपातकाल ने देश को रातों-रात जेल की कोठरी में तब्दील कर दिया। यहां तक कि कुछ बोलना भी अपराध हो गया।

42वें संविधान संशोधन के जरिए अदालतों पर अंकुश लगा दिया गया। साथ ही, संसद और अन्य संस्थाओं को भी नहीं बख्शा गया। जनता की भावनाओं को देखते हुए इस आपातकाल को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसे थोपने वालों की संविधान विरोधी मानसिकता नहीं बदली। कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का लगभग सौ बार इस्तेमाल किया। सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही लगभग पचास बार ऐसा किया। अगर उन्हें कोई राज्य सरकार या नेता पसंद नहीं आता था, तो सरकार को ही बर्खास्त कर दिया जाता था।

अदालतों की अवमानना करने में तो कांग्रेस ने महारत हासिल कर ली है। श्रीमती इंदिरा गांधी ही थीं, जो "Committed Judiciary" यानी 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' चाहती थीं। वो चाहती थीं कि अदालतें संविधान की जगह एक परिवार के प्रति वफादार रहें। 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' की इसी चाहत में कांग्रेस ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते समय कई सम्मानित जजों की अनदेखी की।

कांग्रेस के काम करने का तरीका एकदम साफ है - पहले नकारो, फिर अपमानित करो और इसके बाद धमकाओ। यदि कोई न्यायिक फैसला उनके खिलाफ जाता है, तो वे इसे पहले नकारते हैं, फिर जज को बदनाम करते हैं और उसके बाद जज के खिलाफ महाभियोग लाने में जुट जाते हैं।

सरकारी संस्थान

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी एक टिप्पणी में योजना आयोग को 'A bunch of jokers' यानी 'जोकरों का समूह' कहा था। उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मनमोहन सिंह थे। उनकी इस टिप्पणी से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस सरकारी संस्थाओं के प्रति किस प्रकार की सोच रखती है और कैसा सलूक करती है।

यूपीए शासन के दौर को याद कीजिए, उस समय कांग्रेस ने CAG पर सिर्फ इसलिए सवाल उठाए थे, क्योंकि उसने कांग्रेस सरकार के 2G घोटाला, कोयला घोटाला जैसे भ्रष्टाचार को उजागर किया था। यूपीए शासन के समय में CBI कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनकर रह गई थी। लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के खिलाफ इसका बार-बार दुरुपयोग किया गया। आईबी और RAW जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में जानबूझकर तनाव पैदा किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को एक ऐसे व्यक्ति ने फाड़ दिया था, जो कैबिनेट का सदस्य भी नहीं था और वह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। NAC यानी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को प्रधानमंत्री कार्यालय के समानांतर खड़ा कर दिया गया था और वही कांग्रेस आज संस्थानों की बात करती है।

इतना ही नहीं, जरा याद कीजिए 1990 के दशक में केरल कांग्रेस के राजनीतिक फायदे के लिए देश की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी ISRO में एक काल्पनिक जासूसी कांड की कहानी गढ़ी गई। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि इसका खामियाजा एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और देश को भुगतना पड़ा।

सशस्त्र बल

कांग्रेस हमेशा से रक्षा क्षेत्र को कमाई के एक स्रोत के रूप में देखती आई है। यही कारण है कि हमारे सशस्त्र बलों को कभी भी कांग्रेस से वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। 1947 के बाद से ही कांग्रेस की हर सरकार में तरह-तरह के रक्षा घोटाले होते रहे। घोटालों की इनकी शुरुआत जीप से हुई थी जो तोप, पनडुब्बी और हेलिकॉप्टर तक पहुंच गई। इनमें हर बिचौलिया एक खास परिवार से जुड़ा रहा है।

याद कीजिए, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने जब सेना प्रमुख को गुंडा कहा तो उसके बाद पार्टी में उसका कद बढ़ा दिया गया। इससे पता चलता है कि अपनी सेना के प्रति भी वे कैसा तिरस्कार का भाव रखते हैं। जब हमारी सेना आतंकियों और उसके सरपरस्तों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो कांग्रेस के नेता राजनीतिक नेतृत्व पर 'खून की दलाली' का आरोप लगाते हैं। जब हमारी वायुसेना के जांबाज आतंकियों पर हमला करते हैं, तो कांग्रेस उनके दावे पर सवाल उठाती है।

कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव

राजनीतिक दल उस जीवंत संस्था की तरह होते हैं, जहां भिन्न-भिन्न विचारों का सम्मान होता है, लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र में कोई विश्वास ही नहीं है। अगर कोई नेता पार्टी अध्यक्ष बनने का सपना भी देखे, तो कांग्रेस में उसे फौरन बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।

एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया में भी उनके व्यवहार में घमंड और अधिकार का भाव दिखाई देता है। वर्तमान में उनका शीर्ष नेतृत्व बड़े-बड़े घोटालों में जमानत पर है। जब कभी कोई अथॉरिटी घोटाले से जुड़े सवाल पूछती है, तो वे लोग जवाब देना तक उचित नहीं समझते। क्या वे लोग अपनी जवाबदेही से डरे हुए हैं?

जरा सोचिए
प्रेस से पार्लियामेंट तक।
सोल्जर्स से लेकर फ्री स्पीच तक।
कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक।

संस्थाओं को अपमानित करना कांग्रेस का तरीका रहा है।

उनकी सोच यही है कि सब गलत हैं और सिर्फ कांग्रेस सही है। यानी 'खाता न बही, जो कांग्रेस कहे, वही सही।' जब भी आप वोट देने जाएं, अतीत को एक बार जरूर याद करें कि किस प्रकार एक परिवार की सत्ता की लालसा के चलते देश ने भारी कीमत चुकाई। जब उन्होंने हमेशा ही देश को दांव पर लगाया है तो यह तय है कि अब भी वे ऐसा ही करेंगे।

याद रखिए, अगर हम अपनी स्वतंत्रता बचाए रखना चाहते हैं तो हमें हर पल सतर्क रहना होगा। आइए, हम सजग-सतर्क बनें। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संवैधानिक संस्थाएं हमें सौंपी हैं, उन्हें और मजबूत बनाने का प्रयत्न करें। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण

नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

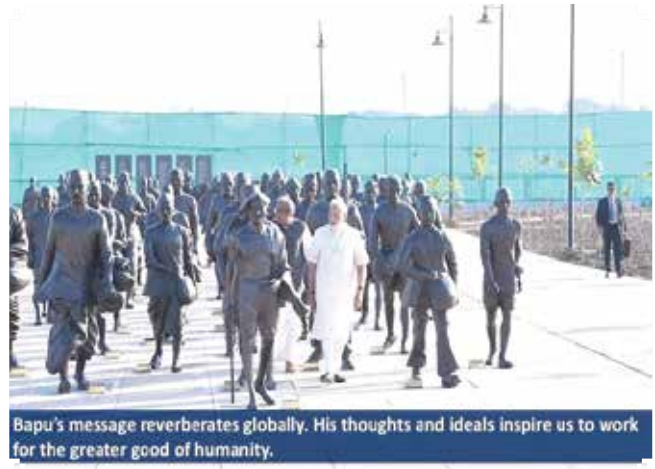

डांडी मार्च की वर्षगांठ पर गांधीनगर (गुजरात) स्थित डांडी संग्रहालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में ऑडियो ब्रिज के जरिए 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित लोगों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-19